दैनिक
सिटी दर्पण
आईना सच का

आज का विचार

खूबसूरत रिश्तों को संभाल कर रखना साहब... अगर यह खो गए तो गूगल से भी नहीं ढूंढ पाओगे।

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । शनिवार, 2 मई, 2026 वर्ष 24, अंक 105, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ आज भी है और 2027 में भी रहेगा : भगवंत सिंह मान

भगवंत मान सरकार ने सर्वसम्मति से जीता विश्वास मत, सीएम बोले- कांग्रेस का सदन में ना होना भी सरकार के विश्वास मत का साथ देना है

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब विधानसभा के फ्लोर को राजनीतिक अधिकार के एक निर्णायक दावे में बदल दिया, जिसमें उनकी सरकार ने सर्वसम्मति से विश्वास प्रस्ताव जीतकर एक स्पष्ट संदेश दिया कि पंजाब सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें नाकाम रहीं। लोगों के जनादेश को दृढ़ विश्वास का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एलान किया कि आम आदमी पार्टी (आप) का बहुमत आधार बरकरार है, जो 2027 में और भी बड़े फैसले से स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने खून-पसीने से बनी पार्टी की जमीनी ताकत और अरविंद केजरीवाल के साथ इसके अटूट बंधन को उजागर किया।

विपक्ष के संबंध में उन्होंने सदन में कांग्रेस की अनुपस्थिति को मौन समर्थन बताया और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए। उन्होंने साथ ही यह एलान करके एक बड़ी संवैधानिक लड़ाई का संकेत दिया कि पंजाब सरकार राष्ट्रपति के पास पहुंचकर दल-बदल विरोधी सख्त कानूनी प्रस्तावों या री-कॉल के अधिकार की मांग करेगी। 'आप' को दल-बदल से प्रभावित न होने वाली एक टिकाऊ राष्ट्रीय ताकत बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि हमारी पार्टी लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे तरीके बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कमजोर करते हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान कुल 88

'आप' विधायक मौजूद थे, जबकि 'आप' के दो विधायक इस समय विदेश में हैं और दो जेल में हैं। इसके अलावा दो विधायक अस्पताल में भर्ती हैं। विश्वास प्रस्ताव को सदन में सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने भगवंत मान सरकार की ताकत और एकता को उजागर किया।विश्वास प्रस्ताव पेश करके विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि गलत और भ्रामक जानकारी के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पंजाब के लोग सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं।उन्होंने कहा कि इन दिनों सूबा सरकार को अस्थिर करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों के मन में शक की भावना पैदा हो रही है। हालांकि, पंजाब के लोगों ने बार-बार सरकार और इसकी नीतियों में स्पष्ट विश्वास दिखाया है।मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरा विपक्ष निराशा के आलम में है क्योंकि उनके नकारात्मक कूड़ प्रचार के बावजूद उन्हें लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा।विपक्ष के आंतरिक कलह पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि विपक्ष पूरी तरह से आपस में ही उलझा हुआ है और उनकी लीडरशिप सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे नेताओं से बंटी हुई है।विपक्ष के नेता और उनका अपना भाई एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनकी पार्टियों के झंडे अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत 'आप' सत्ताधारी 'आप' पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, जिसका हर वॉलिंटियर पंजाब की तरक्की के लिए ठोस यत्न कर रहा है।वैधानिक और राजनीतिक सक्रियताओं के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह हजम नहीं कर पा रही हैं कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पास हो गया है, क्योंकि यह अधिनियम उन्हें अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात से लेकर देश भर में 'आप' की बढ़ती मौजूदगी ने भाजपा और इसके सहयोगियों को बेचैनी में डाल दिया है।

पंजाब में है आज राजनीतिक अस्थिरता: नायब सैनी

कहा- पंजाब में भाजपाकी सरकार बनने पर विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर विकसित पंजाब बनाने का किया जाएगा काम

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज पंजाब की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सत्ता, स्थिरता और जनहित के बीच गहरा संघर्ष दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजनीति में अस्थिरता बढ़ रही है। पंजाब को आज जरूरत है एक ऐसी डबल इंजन सरकार की, जो केवल वादे न करे, बल्कि उन्हें पूरा करने की क्षमता भी रखे। जरूरत है एक ऐसे नेतृत्व की, जो निर्णय लेने से न डरे, जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे और जो देशहित में काम करे। यह सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर विकसित पंजाब बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब के गोबिंदगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ का इतिहास हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और संकल्प से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह क्षेत्र सदियों से व्यापार, संस्कृति और सामाजिक समरसता का केंद्र रहा है। यहां विभिन्न समुदायों ने मिल-जुलकर एक ऐसी विरासत का निर्माण किया है, जिसमें एकता और भाईचारे की भावना सर्वोपरि है। इतिहास के अनेक उतार-चढ़ावों का साक्षी रहा यह नगर हर चुनौती के बाद और अधिक मजबूत होकर उभरा है। चाहे वह सामाजिक परिवर्तन का दौर रहा हो या आर्थिक बदलावों का समय हो, मंडी गोबिंदगढ़ ने हर परिस्थिति में अपनी पहचान और अपने आत्मबल को बनाए रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर देशभर में स्टील टाउन के नाम से भी विख्यात है। यहां के उद्योग पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। विडंबना है कि आज मंडी गोबिंदगढ़ का उद्योग कई गंभीर संकटों से जूझ रहा है। महंगी बिजली और नीतिगत अस्थिरता ने यहां के उद्योगों की रीढ़ को कमजोर किया है। कई छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने की कगार पर हैं और हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, यह उन परिवारों की पीड़ा है, जिनकी रोजी-रोटी इस उद्योग से जुड़ी हुई है। जब फैक्ट्री बंद होती है, तो केवल मशीनें नहीं रुकतीं, बल्कि घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के अपने संकल्प-पत्र के 217 में से 60 वादों को डेढ़ साल में ही पूरा कर दिखाया है।यही नहीं, 157 वादों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बहनों-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ह्यदीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजनाह्न शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक लगभग 10 लाख बहन-बेटियों को 1 हजार 38 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 79 हजार 317 करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बुजुर्गों को 3200 रुपये प्रति माह पेंशन दे रही है। इस पेंशन का 50 लाख बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में ह्यबिना पर्ची और बिना खर्चीह्न के 2 लाख युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब के कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब से नशा खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज पंजाब विधानसभा में दिए जा रहे भाषण के समय मुख्यमंत्री स्वयं नशे में दिखाई दिए। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक कंवरवीर सिंह टोहरा, राज्य सभा सदस्य सरदार सतनाम सिंह संधू, हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल, पंजाब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा, जिला प्रधान भाजपा दीदार सिंह भट्टी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश गुप्ता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था में शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी: योगी

सिटी दर्पण संवाददाता
लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने प्रदेश में भीषण गर्मी और इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए शासन-प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और राहत प्रबंधन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी विभाग परिस्थितियों का पूवार्नुमान लगाकर अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्रीने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पूर्व में सूखा प्रभावित रहे 18 जनपदों में विशेष निगरानी रखने, आगामी 15 जून से 30 जुलाई के बीच निर्धारित मानकों के अनुसार स्थिति का समयबद्ध आकलन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर एन0डी0आर0एफ0 से सहायता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन से लेकर जनपद स्तर तक कंट्रोल रूम सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यक जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव और डी0जी0पी0 को उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्रीने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की निरंतर मॉनिटरिंग करने और जल संरक्षण को गति देने के लिए आगामी 30 मई तक नहरों, तालाबों एवं पोखरों की डी-सिल्टिंग पूर्ण करा ली जाए। साथ ही, तालाबों से निकली मिट्टी प्रजापति समाज, पारम्परिक कुम्हार एवं शिल्पकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराने तथा इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राहत कार्यों के साथ आजीविका के अवसर भी सृजित हो सकें। मुख्यमंत्रीने निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए।

पाइप्ड पेयजल योजनाओं के साथ वैकल्पिक व्यवस्थाएं, जैसे टैंकर आदि, पूरी तरह तैयार रखे जाएं।उन्होंने वन विभाग को अभ्यारण्यों एवं पक्षी विहारों में वन्यजीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में जल, चारा एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्रीने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, सभी नलकूपों को क्रियाशील रखने, समय से मरम्मत सुनिश्चित करने तथा सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जल के वैज्ञानिक एवं संतुलित उपयोग पर बल देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में जल की कमी न हो और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए। मुख्यमंत्री ने फसल सुरक्षा के दृष्टिगत अनुदानित बीज वितरण तथा कृषि परामर्श के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि नुकसान की स्थिति में समयबद्ध आकलन एवं क्लेम निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रपति ने शिमला में सेना के जवानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की जानकारी ली

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

हिमाचल दौरे पर गईं भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय का दौरा किया। उन्हें यहां भारतीय सेना के जवानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के बारे में ट्रेनिंग कमांड की शानदार भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।

ट्रेनिंग कमांड के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपति को यहां के विकास, परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के जवानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में बताया। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की नई पहलों के बारे में बताते हुए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने ड्रोन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने, खास तकनीक को अपनाने के लिए उठाए गए कदमों, ह्यरेड टीमिंगह्न के कॉन्सेप्ट की शुरूआत और भारतीय सेना में डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की दिशा में की गई पहलों के बारे में बताया।

राष्ट्रपति ने माना कि ट्रेनिंग कमांड की युद्ध की अवधारणा को डिजाइन करने, भारतीय सेना के लिए संसाधन विकास और मित्र देशों के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ाव में एक अहम भूमिका है।यह सैन्य गौरव, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के रास्ते में जरूरी पहल है।सेना का यह ट्रेनिंग कमांड अपने 32 सबसे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए भारतीय सेना में व्यावसायिकता के क्षेत्र को मजबूत करता है, जो इसे युद्ध लड़ने की कला और विज्ञान में एक अनोखा नजरिया देता है।

राष्ट्रपति ने देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना में ट्रेनिंग पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता की मौजूदगी में लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा के साथ विचारों का आदान-प्रदान भी किया। राष्ट्रपति ने कमांड से भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने के लिए जोश के साथ काम करते रहने की अपील की।

राजस्थान के युवा मेहनत, नवाचार और बहुभाषी कौशल से वैश्विक अवसरों के लिए तैयार : प्रधान

एजेंसी (हि.स.)
जयपुर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राजस्थान के युवाओं में मेहनत, नवाचार, उद्यमिता और विविध भाषाओं एवं संस्कृतियों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का युवा अब केवल डिग्री और प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बहुआयामी अवसरों की ओर अग्रसर हो रहा है।

जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के एमओयू समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को बहुभाषी, आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस नीति के तहत युवाओं को मातृभाषा के साथ-साथ विदेशी भाषाओं का ज्ञान देकर उन्हें विश्वस्तरीय अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और वैश्विक समझ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। फ्रेंच, जर्मन, जापानी, कोरियन और स्पेनिश जैसी भाषाओं का अध्ययन युवाओं के लिए रोजगार, व्यापार, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नए द्वार खोलेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एशियाई देशों के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों के चलते विदेशी भाषा दक्षता रखने वाले युवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी। जापान, कोरिया और यूरोपीय देशों में न केवल सॉफ्टवेयर, बल्कि हार्ड ट्रेड, तकनीकी सेवाओं, मार्केटिंग और आतिथ्य क्षेत्र में भी भारतीय युवाओं के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

शिवराज चौहान ने ओडिशा को दी पीएमजीएसवाई के तहत 1,700 करोड़ रु. से 827 नई सड़कों की सौगात

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

ओडिशा के रायगड़ा में आज आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ मिलकर सड़क, आवास, सिंचाई, रोजगार, पेयजल, महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि से जुड़े अनेक सौगातें दीं।केंद्रीय मंत्री चौहान ने मंच पर ही पीएमजीएसवाई- 4का स्वीकृति-पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा, विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ/शिलान्यास हुआ और हितग्राहियों को सहायता प्रदान की गई।

रायगड़ा के बरिजोला में आयोजित इस भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा, विशेषकर रायगड़ा की सांस्कृतिक गरिमा, प्राकृतिक सौंदर्य और परिश्रमी जनता की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि वे आज खाली हाथ नहीं आए बल्कि ओडिशा के लिए विकास की ठोस सौगातें लेकर आए हैं, जिनका सीधा लाभ गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं तक पहुँचेगा। चौहान ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि जिंदगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र प्रगति की जीवनरेखा हैं। इसी सोच के अनुरूप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-क्ष्र के प्रथम चरण में ओडिशा के लिए 1,698.04 करोड़ रुपये की लागत से 1701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 नई सड़कों की सौगात दी गई है। साथ ही, पूर्व स्वीकृत लेकिन अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी दूरस्थ क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे।केंद्रीय मंत्री चौहान ने पीएमजीएसवाई-4का स्वीकृति-पत्र मुख्यमंत्री माझी को मंच पर सौंपा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आवास और आजीविका पर विशेष बल देते हुए कहा कि ओडिशा में कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा और हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ढटअ-ॠ के अंतर्गत लंबित आवासों को पूरा करने के लिए 630.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर उन्होंने मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम किश्त के रूप में 868.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया।

शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं, किसानों और युवाओं को विकास के केंद्र में रखते हुए कहा कि गरीब बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वावलंबन और आर्थिक सशक्तिकरण देना सरकार का संकल्प है। उन्होंने लखपति दीदी अभियान, स्वयं सहायता समूहों की उन्नति, ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार प्रशिक्षण, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकीकृत खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, बकरीपालन, मधुमक्खी पालन और वृक्षारोपण आधारित आय-वृद्धि के उपायों पर जोर दिया।उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा में प्रगतिशील खेती, बेहतर बीज, सीड विलेज, भंडारण क्षमता और एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से गोदाम निर्माण जैसे कदम किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करते हुए कहा कि इतनी सौगात ओडिशा के प्रति केंद्र सरकार के विशेष स्नेह और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और आज उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण भारत की दशा और दिशा बदलने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पीएमजीएसवाई- 4को विशेष रूप से दुर्गम, पहाड़ी, दूरस्थ और अब तक संपर्क से वंचित क्षेत्रों को जोड़ने वाला परिवर्तनकारी कदम बताया।

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि राज्य सरकार ह्लसमृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशाह्व के संकल्प के साथ सड़क, पुल, पेयजल, बिजली, ग्रामीण आधारभूत ढाँचा, किसानों की आय, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि रायगड़ा सहित राज्य के अनेक जिलों में सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाएँ ग्रामीण जीवन को नई दिशा देंगी।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के हाथों हितग्राहियों का सम्मान और सहायता राशि का वितरण भी हुआ। इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज व पेयजल मंत्री रबी नारायण नायक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्यजन तथा बड़ी संख्या में महिलाओं सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित थे।

लद्दाख में बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ, अमित शाह बोले- शांति व सहअस्तित्व का संदेश और प्रासंगिक

75 साल बाद लद्दाख की धरती पर लौटे पावन अवशेषः शाह

एजेंसी (हि.स.)
लेह

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख में भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली राष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 वर्षों के बाद इन अवशेषों का लद्दाख आगमन ऐतिहासिक और सौभाग्यपूर्ण क्षण है, जो पूरी मानवता को शांति, सहअस्तित्व एवं मध्यम मार्ग का संदेश देता है। भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से ज्ञान और करुणा पर आधारित रही है और आज बुद्ध के संदेश की प्रासंगिकता पहले से अधिक बढ़ गई है।

यहां धार्मिक कार्यक्रम स्थल जिवेत्सल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष त्सेरिंग दोरजे लाकरूक, लद्दाख गोंपा संघ के अध्यक्ष दोरजे स्टांजिन, रिनपोछे क्याबजे द्रुक्पा थुकसे, डॉ लोबजांग त्सेवांग सहित बौद्ध समुदाय के कई प्रमुख

विकास और सुरक्षा पर भी दिया जोर

धार्मिक नेता, आध्यात्मिक गुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लामा वादन, त्सोग अर्पण, दीप प्रज्वलन और पवित्र अवशेषों के दर्शन कराए गए। साथ ही तिब्बती सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीत और लद्दाखी लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिनमें क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि आज से 563 ईसा पूर्व लुंबिनी में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे तथागत बुद्ध कहलाए और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे संयोग इतिहास में विरले ही देखने को मिलते हैं, जिसका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक ही दिन हुए हों। इससे बुद्ध का जीवन और उनका संदेश और अधिक विशिष्ट बन जाता है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पहले जब बुद्ध के

अवशेष यहां लाए गए होंगे, तब बुनियादी सुविधाएं सीमित रही होंगी, लेकिन आज विकसित अवसंरचना के बीच इन अवशेषों का आगमन नए युग का प्रतीक है। यह दिन लद्दाख के लोगों के लिए विशेष सौभाग्य का दिन है और यह ऐतिहासिक मिलन का क्षण है, जब तथागत बुद्ध की स्मृतियां पुनः इस भूमि से जुड़ रही हैं। अमित शाह ने कहा कि लद्दाख बुद्ध के धम्म की भूमि रही है और यहां सदियों से उनके विचारों का संरक्षण और संवर्धन होता रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो वे इस भूमि को बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला बताते हैं। कठिन समय में इस क्षेत्र ने बुद्ध के ज्ञान को सुरक्षित रखा और अनुकूल समय में उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि निंगमा, काग्यु, साक्य और गेलुग जैसी परंपराओं का मूल संदेश वस्तु को उसी रूप में देखने का है जैसा वह है। यह दृष्टिकोण वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब दुनिया संघर्ष और अस्थिरता का सामना कर रही है। गृहमंत्री ने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति यह स्मरण कराती है कि भारत की सभ्यता शांति और सहअस्तित्व के मूल्यों पर आधारित है।

युद्ध और संघर्ष के समय में भी शांति का मार्ग ही मानवता को आगे बढ़ा सकता है और यही बुद्ध का संदेश है। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर से तिब्बत जाने वाले मार्गों के माध्यम से लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। साथ ही सिल्क रूट के कारण यह क्षेत्र व्यापार के साथ-साथ विचारों के आदान-प्रदान का भी प्रमुख केंद्र बना। आज भी विश्व में जहां-जहां बौद्ध परंपरा मौजूद है, वहां लद्दाख से जुड़े ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है। अमित शाह ने कहा कि जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तब उनका संदेश जितना प्रासंगिक था, आज वह उससे अधिक प्रासंगिक हो गया है।

पूरी दुनिया बुद्ध के संदेश को समझेगी और मध्यम मार्ग को अपनाकर शांति और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि आज लद्दाख में उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाया है। यह आयोजन दुनिया भर के लोगों, पर्यटकों और आध्यात्मिक नेताओं को एक मंच पर लाकर वैश्विक शांति के संदेश को सशक्त बना रहा है।

भाजपा ने कांगड़ा में बनाई जीत की रणनीति

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

कांगड़ा में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को आगामी नगर निगम, नगर निकाय और जिला परिषद चुनावों के लिए रणनीति तैयार की। यह बैठक मटौर स्थित भाजपा विधायक पवन काजल के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, डॉ. राजीव भारद्वाज, विक्रम ठाकुर, रविंद्र रवि, अरुण कुक्का और जिला भाजपा अध्यक्ष सचिन शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

बंद कमरे में लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में चुनावी तैयारियों पर गहन मंथन हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और उनकी टीम के धर्मशाला और कांगड़ा दौरे के ठीक एक दिन बाद हुई इस भाजपा बैठक से क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी का मुख्य ध्यान धर्मशाला और पालमपुर नगर निगमों पर रहा, जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है।

इन दोनों नगर निगमों में जीत सनिश्रित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहन मंथन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रभारी पवन काजल और जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा से फीडबैक लिया। बैठक में जिला परिषद चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की

जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने पर भी चर्चा हुई।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे नगर निगम, निकाय और जिला परिषद चुनावों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करें। उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और बेरोजगारों को स्थायी रोजगार न मिलने जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस सरकार को घेरने पर जोर दिया।

सांसद अनुराग ठाकुर ने भी धर्मशाला नगर निगम में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर पर चुनाव प्रचार करने को कहा। उन्होंने पार्टी हित में धर्मशाला में पार्टी अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं से नामांकन वापस लेने की अपील की।

जिला भाजपा अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि जिला परिषद के विभिन्न वार्डों से पार्टी के उम्मीदवार जल्द ही घोषित किए जाएंगे।

संसद टीवी के संवाद में दिखेगा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा का सफर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संवाद में इस बार मिलिए, कार्यक्रम में मंडी जिले की बल्ह घाटी के गांव बैहना के वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश चंद धीमान नजर आएंगे। संसद टीवी की ओर से जारी कार्यक्रम व सूचना के अनुसार संसद टीवी एवं संवाद टीवी पर यह कार्यक्रम पहली मई को शाम 7 बजे, 2 मई को सुबह 9 बजे और 3 मई को दोपहर साढ़े 12 बजे प्रसारित होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से ही संबंध रखने वाले पवन कुमार शर्मा व उनकी टीम जो इन दिनों पहाड़ी भाषा व बोलियों को लेकर कार्य कर रही है ने प्रकाश चंद धीमान का साक्षात्कार 4 मार्च को उनके बैहना स्थित आवास में किया था। पवन कुमार शर्मा ने कहा कि प्रकाश चंद धीमान हिमाचली भाषा के एक ऐसे अद्वितीय संवाहक, संपादक और साहित्कार जिन्होंने 36 वर्ष पूर्व 1990 में पहाड़ी भाषा त्रैमासिक पत्रिका बागर का संपादन शुरू किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध भाषाई विविधता एवं पहाड़ी

बोलियों -कांगड़ी, मंडयाली, कुल्लवी, चंबयाली, सिरमौरी, कहलूरी, बिलासपुरी, महासूई, सुरही, भटियाली, पांगी, किन्नौरी और लाहौली में लेखन को प्रोत्साहित किया। बागर के माध्यम से उन्होंने लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक साहित्य और लोक परंपराओं एवं आंचलिक कविताओं और कहानियों को समृद्ध किया। कार्यक्रम प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि संसद टीवी पर देखिए: पहाड़ी भाषा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए पूरी तरह से समर्पित एवं हिमाचली भाषा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए पूरी तरह से समर्पित एवं हिमाचली पहाड़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान देने की मांग को बुलंद करने वाले रिटायर्ड शिक्षक एवं प्रधानाचार्य प्रकाश चंद धीमान से विशेष बातचीत प्रसारित होगी।

कठुआ में नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, अवैध दवाइयां बेचने वाली मेडिकल शॉप सील

कठुआ। जम्मू-कश्मीर में चल रहे 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के तहत कठुआ प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चकदेसा सिंह क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। यह कार्रवाई शुक्रवार को तहसीलदार कठुआ विक्रम शर्मा की अगुवाई में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कठुआ शहर के समीप चकदेसा सिंह क्षेत्र में संचालित ह्लसमृद्धि मेडिकोजह्व नामक दुकान पर अवैध रूप से ऐसी दवाइयों की बिक्री की जा रही थी, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेचना प्रतिबंधित है। दुकान के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही दुकानदार मौके से कुछ दवाइयां लेकर फरार हो गया और दुकान खुली छोड़ दी। जांच के दौरान दुकान में आवश्यक रिकॉर्ड, कंप्यूटर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं पाए गए। टीम ने मौके से संदिग्ध कैप्सूल बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया। तहसीलदार विक्रम शर्मा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने और अवैध दवाइयों की बिक्री के चलते दुकान को सील किया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में केवल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर्याप्त नहीं है, बल्कि जन सहयोग भी बेहद जरूरी है

हिमाचल लोकभवन में मनाया गया गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित लोक भवन में शुक्रवार को गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के अवसर पर एक गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिस्सा लिया और हिमाचल में रह रहे दोनों राज्यों के लोगों को इस मौके पर एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक मेलजोल के साथ इस दिन को मनाने का संदेश दिया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन अलग-अलग राज्यों के लोगों को एक मंच पर लाते हैं और आपसी समझ तथा सौहार्द को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है और इसे मजबूत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से मिल-जुलकर देश की इस भावना को

आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़े प्रतिभागियों ने राज्यपाल के साथ संवाद किया और अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों के बारे में जानकारी साझा की। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा भी हुई, जिससे कार्यक्रम एक संवाद के मंच के रूप में उभरा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि इनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों के बीच आपसी सम्मान, समझ और सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम के विचार का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति की मूल भावना है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कार्यक्रम में शामिल अतिथियों को हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि लोक भवन में इस तरह के आयोजन लोगों को एक-दूसरे को करीब से समझने और देश की सांस्कृतिक विविधता को सराहने का अवसर देते हैं।

जम्मू शहर के बाहरी इलाके बंतलाब में एक छोटे पुल का एक हिस्सा ढहा

जम्मू। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके बंतलाब क्षेत्र में एक छोटे पुल का एक हिस्सा ढह गया जिससे कम से कम तीन से चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए जबकि एक घायल मजदूर को बचा लिया गया। पुल का हिस्सा गिरने के बाद अधिकारियों ने सड़क संपर्क बंद कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब मजदूर पुल के पास एक रिटेनिंग दीवार की मरम्मत कर रहे थे जो पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। सूत्रों के अनुसार पुल का एक हिस्सा अचानक टूट गया जिससे काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। पुलिस, सेना और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने एक घायल मजदूर को बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर मौजूद मजदूरों के परिवार वालों ने बताया कि घटना के समय काम कर रहे लगभग छह मजदूर मलबे के नीचे दब गए। परिवार वालों ने बताया कि दो मजदूर भागने में सफल रहे जबकि चार फंस गए। सूत्रों के अनुसार मलबे में फंसे लोगों में एक महिला मजदूर का पति, एक राजमिस्त्री, एक अविवाहित मजदूर और ठेकेदार का एक रिश्तेदार शामिल हैं।

नाहन में बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम, नेताओं और समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

भगवान बुद्ध जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर शहर में लोगों ने भगवान बुद्ध के संदेशों को याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।

इस आयोजन के तहत नाहन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने समाज को शांति, अहिंसा और सद्भाव का रास्ता दिखाया। उनके विचार आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं और लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं इसके बाद जिला सिरमौर कोली समाज समिति ने भी कार्यक्रम आयोजित किया। समिति के जिला अध्यक्ष जीत सिंह चौहान के नेतृत्व में समाज के लोगों ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के सदस्य मौजूद रहे और सभी ने भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को याद किया। समिति के अध्यक्ष जीत सिंह चौहान ने बताया कि बुद्ध जयंती के अवसर पर केवल माल्यार्पण ही नहीं, बल्कि कई अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय प्रवास से दिल्ली लौटीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश के पांच दिवसीय प्रवास के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार दोपहर दिल्ली लौट गईं। शिमला के अन्नाडेल हेलीपैड पर उन्हें गर्मजोशी के साथ विदाई दी गई। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रपति को विदाई देने के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी और प्रशासन, पुलिस व सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले राष्ट्रपति ने शिमला में सेना के प्रशिक्षण कमान का दौरा भी किया, जहां राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 27 अप्रैल को दिल्ली से शिमला पहुंची थीं और इस दौरान उन्होंने अपना अधिकतर समय मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में बिताया। हालांकि, उनके पूरे प्रवास के दौरान मौसम खराब बना रहा, जिसके चलते उनके कई प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करने पड़े। राष्ट्रपति का कुल्लू जिले में अटल टनल और लाहौल-स्पीति के सिस्सू जाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह दौरा नहीं हो सका। इसके अलावा कांगड़ा जिले के पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम भी मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। शिमला प्रवास के दौरान राष्ट्रपति उनके सम्मान में लोकभवन में आयोजित राज्य भोज में भी शामिल हुईं। वहीं, मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास में 'एट होम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। पांच दिन के इस दौरे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज दिल्ली के लिए रवाना हो गईं।

अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भाजपा ने किया स्वागत

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के एक पुराने बयान से जुड़े मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे न्याय प्रक्रिया पर भरोसे की मजबूती बताया है। यह बात जिला भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कही।

प्रवक्ता के अनुसार अनुराग ठाकुर के उस बयान को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने देश के गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई थी और मामला अदालत तक पहुंचा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने वामपंथी नेता वृंदा करात की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में भाजपा नेता प्रवेश साहिब

वर्मा को भी राहत मिली है। विनोद ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अनुराग ठाकुर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे को उठाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा न्यायालय और न्याय प्रक्रिया का सम्मान करती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमेशा देशहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी है और उनके बयान देश की एकता और मजबूती के पक्ष में रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से मिली यह राहत इस बात का संकेत है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है।

मौसम | **आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी**

हिमाचल में फिर ओलावृष्टि, 6 मई तक खराब मौसम की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है और आने वाले दिनों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा पूवार्नुमान के अनुसार 3 और 4 मई को राज्य के कई हिस्सों में मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है, जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और फलों को नुकसान हो सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार 2 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। 3 मई को लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी जिलों में अलर्ट रहेगा।

चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 4 मई को भी लगभग यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 5 और 6 मई को कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। जुब्बरहट्टी में सबसे ज्यादा 34 मिमी वर्षा हुई, जबकि शिमला में 15.8 मिमी, कसौली में 11 मिमी, जट्टन बैराज में 9.4 मिमी और नाहन में 9.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान शिमला, जुब्बरहट्टी और कुफरी सहित कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि बर्फबारी कहीं दर्ज नहीं की गई। तापमान की बात करें तो राज्य में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। कई स्थानों पर ठंड का एहसास बना हुआ है। ताबो में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम रहा। कल्पा में 5.8, मनाली में 8.1, शिमला में 12.0, सोलन में 11.7, पालमपुर में 15.0, कांगड़ा में 16.7, मंडी में 16.3 और ऊना में 18.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम के बदले तेवरों के कारण शिमला और मनाली में ठंड महसूस की जा रही है, जबकि मैदानी इलाकों में भी गर्मी का असर कम हुआ है। फिलहाल शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है और निचले इलाकों में तेज धूप रही। लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि मई के शुरूआती दिनों में मौसम फिर बिगड़ेगा। इस साल अप्रैल महीने में भी हिमाचल में अच्छी बारिश दर्ज की गई और कुल वर्षा सामान्य से करीब 1 प्रतिशत अधिक रही। अब मई महीने में भी बादलों के बरसने का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है, जिससे एक ओर जहां गर्मी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर मौसम की मार किसानों और बागवानों पर भारी पड़ सकती है।

संक्षिप्त-समाचार

लाखों रुपये के सरकारी नौकरी धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल

श्रीनगर। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की कश्मीर विशेष अपराध शाखा ने लाखों रुपये के सरकारी नौकरी धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। आरपीसी की धारा 201, 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 09/2019 में तीन आरोपियों - मालोरा शाल्टेंग श्रीनगर के फैयाज अहमद खान, शान्जीपोरा हंदवाडा के शौकत अहमद शाह और शाल्टेंग ख्वाजा बाग के ओवैस अहमद राथर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। यह मामला पुलवामा के निवासियों की शिकायत से जुड़ा है जिन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उनसे लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर प्रभावशाली अधिकारियों का रूप धारण किया और वन विभाग से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए। बाद में इन दस्तावेजों की जांच की गई और वे जाली पाए गए। आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने पीड़ितों से भारी मात्रा में नकद राशि वसूल की थी। अधिकारियों ने बताया कि चालान को न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

चार बीघा भूमि में 1.38 लाख अफीम के पौधे किए नष्ट

मंडी। प्रदेश सरकार की ओर से चिट्टा-मुक्त हिमाचल को जनादोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को एसटीएफ मंडी ने द्रंग क्षेत्र के इलाका उतरशाल में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दुर्गम क्षेत्र होने के चलते पुलिस टीम ने रात के अंधेरे में जोखिम उठाते हुए मौके तक पहुंचकर दबिश दी। टीम को इलाका उत्तरशाल के अंतर्गत सिलसुलहरी उप-तहसील कटौला में अवैध खेती की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान निजी भूमि पर करीब 10 खेतों में फैली लगभग चार बीघा जमीन पर अवैध अफीम की खेती पाई गई। यहां से करीब 1,38,655 अफीम के पौधे बरामद किए गए, जिन्हें टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। कई साल पूर्व मंडी जिला की चौहारघाटी में अफीम की खेती को लेकर इसी तरह का अभियान चलाया गया था। अब इतने सालों के बाद चौहारघाटी के साथ लगते दुर्गम क्षेत्र उतरशाल में यह अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में थाना पधर, जिला मंडी में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अभी जारी है। थाना प्रभारी पधर अनिल कटोच ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध अफीम की खेती पर प्रभावी रोक लगाना, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।

सोलन में शिकार के दौरान चली गोली से मौत, आरोपी गिरफ्तार

सोलन। सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में जंगल में शिकार के दौरान चली गोली से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार यह घटना 29 अप्रैल की है। गांव जमरोटी निवासी राहुल ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसे कमलजीत का फोन आया, जिसमें बताया गया कि उसके पिता लक्ष्मीकांत को जंगल में चोट लग गई है। सूचना मिलने के बाद राहुल अपने परिचित भगत राम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां उसके पिता घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर के पीछे बाईं ओर कुल्हे के पास गोली लगी थी और काफी खून बह चुका था। परिजन तुरंत लक्ष्मीकांत को अर्की अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए। शव का पोस्टमार्टम शिमला के आईजीएमसी में करवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लक्ष्मीकांत और रणजीत सिंह जंगल में शिकार के लिए गए थे। इसी दौरान रणजीत सिंह का पैर फिसल गया, जिससे उसकी बंदूक से अचानक गोली चल गई और वह लक्ष्मीकांत को जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रणजीत सिंह (62) को को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। सोलन के पुलिस अधीक्षक साईं दत्तात्रेय ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अमरनाथ यात्रा' के लिए सीआरपीएफ ने एनएच-44 पर की कड़ी सुरक्षा

जम्मू। श्री अमरनाथ यात्रा व सचिवालय के कर्मचारियों और अभिलेखों को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरण' के मद्देनजर सीआरपीएफ की 84 बटालियन ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है। सचिवालय के कर्मचारी 30 अप्रैल की सुबह से जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो चुके हैं ताकि 4 मई को श्रीनगर सचिवालय में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हो सकें। रामबन के चंदरकोट क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ की 84 बटालियन का अधिकार क्षेत्र नशरी में स्थित 9.8 किलोमीटर लंबी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग से लेकर डिगडोल तक फैले एनएच-44 के 47 किलोमीटर के क्षेत्र पर है। बटालियन ने राजमार्ग पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण सामरिक और रणनीतिक दृष्टि बिंदुओं पर, अपने जवानों को पूरी ताकत से तैनात किया है। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के कमांडेंट एन रणबीर सिंह ने कहा, हर साल की तरह, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 'दरबार मूव' की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्योन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

मोदी के नेतृत्व को मजबूत करो, पंजाब को भी मजबूत करेंगे : नायब सिंह सैनी

पंजाब का उद्योगपति कई चुनौतियों से जूझ रहा , बिजली संकट, लॉ एंड ऑर्डर और नीतिगत अस्थिरता

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के लोगों से आह्वान किया कि वे मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करें, फिर पंजाब को भी मजबूत करेंगे।पिछली सरकारों ने पंजाब को कंगला बनाया है, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद इसको पुनः रंगीला पंजाब बनाया जाएगा।श्री सैनी पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ शहर में उद्योगपतियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा जहां अपने प्रदेश के उद्योगों के लिए कई सहूलियतें प्रदान कर रहा है वहीं कुछ राज्य सरकारें आज भी राजनीति में उलझी हुई हैं। वे विकास की बजाय टकराव की राजनीति करती हैं।उद्योगों को बढ़ावा देने की बजाय वे उन्हें नियमों के जाल में फंसा देती हैं।ऐसे हालात आप रोजाना पंजाब में देख ही रहे हैं। कैसे उद्योगपतियों, कारोबारियों, यहां तक की उद्योग जगत की समस्याओं को उजागर करने वाले मीडिया संस्थानों को भी डराया धमकाया जा रहा है?

उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में पिछले साढ़े 11 वर्षों में जिस तरह उद्योगों को बढ़ावा दिया है, वह किसी से छिपा नहीं है। हमने नीतियों को सरल बनाया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया। बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन, अगर हम पंजाब की ओर देखें, तो स्थिति कुछ अलग नजर आती है।यहां उद्योगपति आज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिजली संकट, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या व नीतिगत अस्थिरता। लेकिन, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मगर सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश के औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उद्योगपतियों से विचार -विमर्श करके उनके सुझावों के आधार पर ही उद्योग नीति बना रहे हैं जो कि देश में नंबर वन होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर उद्योग एवं श्रमिकों के विवाद को परस्पर सहमति एवं भाईचारे से सुलझाने के लिए ₹उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद₹ का गठन किया गया है। उन्होंने हरियाणा को निवेशकों की पहली पसंद बताते हुए कहा कि राज्य में निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु जल्द ही 'लैंड फीज़िबिलिटी सर्टिफिकेट' व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे निवेशकों को 45 दिनों के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आगे बताया कि हरियाणा में कारोबार करने में आसानी के लिए 48 विभागों के 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को समाप्त किया गया है। हम लैंड पूलिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लैंड पूलिंग नीति में संशोधन कर रहे हैं। इससे 10 नए मेगा-स्केल आईएमटी के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राई में आई.एम.टी. विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव मांगे हैं। यही नहीं, आईएमटी अम्बाला और नारायणगढ़ के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा के उद्योग क्षेत्र की विश्व स्तर पर पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।इस दिशा में निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए ₹हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउन्सिलर₹ बनाई है।

श्री सैनी ने जानकारी दी कि नये उद्योगों की स्थापना और उनके शीघ्र परिचालन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 'प्लग-एंड-प्ले' सुविधाओं वाली फैक्ट्रियां और शेड विकसित किए जाएंगे। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई इकाइयों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित रें'' ळ१ीं१२ ल्ला टरटए क्ल्ल२४१ल्ली ग्रीं शुरू की जाएगी, जो आग, चोरी और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध किफायती बीमा कवर प्रदान करेगी। निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु 'एडवांस रुलिंग पोर्टल' बनाया जाएगा, जहां 15 दिनों में समाधान सुनिश्चित होगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा को विशिष्ट उद्योगों का केंद्र बनाने हेतु पानीपत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट कलस्टर विकसित होगा। निर्यातकों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु हम Export Boosters प्रदान करेंगे और Export Freight Subsidy Support को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करेंगे। प्रत्येक जिले में एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क और प्लग-एंड-प्ले क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के उद्योगपतियों को कहा कि पंजाब के सामने एक स्पष्ट विकल्प है। एक तरफ है विकास, स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व है तो दूसरी तरफ अस्थिरता, भ्रम और वादाखिलाफी है। अब आप सबको मिलकर यह तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं।उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा सौंपे गए मांगपत्र को केंद्र सरकार से मिलकर उनके समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाओगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंजाब को भी विकास के मामले में नंबर वन सूबा बना देंगे।इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री असीम गोयल, पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ सुभाष शर्मा, उद्योगपति नारायण सिंगला, महेंद्र गुप्ता, विनोद वशिष्ठ, प्रदीप गर्ग समेत अनेक उद्योगपति एवं भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे।

गेहूं खरीद मानकों में विशेष छूट से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत: श्याम सिंह राणा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

किसानों के हित में केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला : कृषि मंत्री

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष उठाने का परिणाम है।कृषि मंत्री ने बताया कि हाल ही में असमय वर्षा के कारण हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से खरीद मानकों में विशेष छूट प्रदान की।उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए निम्नलिखित राहतें लागू की गई हैं—लस्टर लॉस (चमक की कमी) की सीमा 70% तक बढ़ाई गई है, सिकुड़े एवं टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% की गई है और क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6% निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय रबी विपणन सीजन की शुरूआत से ही लागू कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री राणा ने कहा कि इस फैसले से किसानों को अपनी उपज पर कटौती से राहत मिलेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग से भंडारण और प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

हरियाणा में 52,000 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में जनगणना एवं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा राज्य के 52,000 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में जनगणना एवं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का विधिवत शुभारंभ हो गया। यह कार्य प्रशिक्षित प्रगणकों द्वारा किया जा रहा है, जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी हैं। पिछले एक माह के दौरान सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि जनगणना कार्य सुचारु, सटीक एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हो सके।

इस बार की जनगणना पूर्णतः डिजिटल होगी और संपूर्ण हाउस लिस्टिंग एवं डेटा संकलन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। जिन नागरिकों ने पहले सेल्फ-एन्यूमरेशन कर लिया है, उन्हें केवल अपनी स्वगणना क्रूप्रगणक को बतानी होगी। आज से प्रारंभ हुए ऑपरेशंस में प्रगणकों द्वारा मकानों पर क्रमवार संख्या अंकित की जा रही है।प्रत्येक एन्यूमरेशन ब्लॉक में मकानों को सीरियल नंबर से चिन्हित किया जाएगा। सेक्टर आधारित आवासीय क्षेत्रों में सेक्टर नंबर एवं मकान संख्या को ही अंकन हेतु प्रयोग किया जाएगा। साथ ही, प्रगणक अपने क्षेत्र की प्रत्येक गली, मोहल्ले एवं बस्ती का सर्वेक्षण कर नजरी नक्शा तैयार करेंगे, ताकि कोई भी मकान अथवा परिवार जनगणना से वंचित न रहे।

निदेशक जनगणना, हरियाणा, डॉ. ललित जैन ने प्रदेशवासियों से प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स को पूर्ण सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक संदेह होने पर संबंधित अधिकारी का पहचान पत्र जांच सकते हैं, जिस पर स्कैन कोड भी उपलब्ध है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि प्रगणकों का सम्मानपूर्वक स्वागत करें तथा सही एवं सटीक जानकारी दें। पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों से भी सहयोग का अनुरोध किया गया, क्योंकि यह राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण कार्य है।

डॉ. जैन ने कहा, प्रगणक एवं सुपरवाइजर जनगणना विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और पूरा विभाग उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1885 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है, जिसका उपयोग नागरिक, प्रगणक एवं सुपरवाइजर कर सकते हैं। चूंकि यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है, इसलिए प्रारंभिक चरण में कुछ तकनीकी चुनौतियाँ स्वाभाविक हैं, जिनका विभाग तत्काल समाधान कर रहा है।

उन्होंने प्रगणकों एवं सुपरवाइजर्स से मौसम को ध्यान में रखते हुए फील्ड में जाने तथा पानी एवं टोपी साथ रखने का आग्रह किया। अंत में डॉ. जैन ने चार्ज ऑफिसर के रूप में कार्यरत तहसीलदारों, सचिवों, कार्यकारी अधिकारियों एवं जोनल टैक्सेशन अधिकारियों का विशेष धन्यवाद किया, जो जनगणना अभियान को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

नूंह में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर राज्यपाल ने दिया बल

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष ने जिला नूंह के लघु सचिवालय स्थित सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकासात्मक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले के समग्र विकास के लिए ठोस एवं समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी नागरिक अपनी समस्याओं के साथ प्रशासन के पास आते हैं, उन्हें उचित सुनवाई और संतोषजनक समाधान मिले, जिससे जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग करने और कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले के आधारभूत ढांचे जैसे सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता जताई। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी भवन केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होते, बल्कि यह सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों का प्रतीक हैं। इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखते हुए आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा विद्यार्थियों में अंग्रेजी एवं आधुनिक विषयों की दक्षता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।

तृप्ति श्योराण बनीं हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भिवानी निवासी सुश्री तृप्ति श्योराण को हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इस बारे में हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। तृप्ति श्योराण भिवानी जिले के गांव गागड़वास निवासी हरियाणा को-ऑपरेटिव बैंक भिवानी के सहायक प्रबंधक रहे स्वर्गीय हरिपाल श्योराण की बेटी हैं। उल्लेखनीय है कि तृप्ति श्योराण का जन्म 19 अगस्त, 1989 में हरिपाल श्योराण के घर पुष्पा देवी की कोख से हुआ। तृप्ति श्योराण की नियुक्ति को महिला नेतृत्व एवं सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने वाली पहल माना जा रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए होता है।

शारीरिक माप परीक्षण हेतु व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित, 20,000 अभ्यर्थियों ने अब तक दिया परीक्षण

चंडीगढ़। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य एवं नोडल अधिकारी श्री भूपेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित शारीरिक माप परीक्षण के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह द्वारा परीक्षा व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है तथा आयोग के दो सदस्य भी प्रतिदिन सुचारु रूप से प्रबंधन देख रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रही है। श्री चौहान ने बताया कि 20 से 30 अप्रैल के बीच लगभग 20,000 अभ्यर्थियों ने शारीरिक माप परीक्षण में भाग लिया है। वर्तमान में यह परीक्षण प्रक्रिया जारी है।इस पूरी प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए लगभग 250 अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अग्निशमन विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जीरकपुर बस स्टैंड से ताऊ देवीलाल स्टेडियम तक सुबह 5:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है।

पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में गुरुग्राम में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन व पर्यावरणीय नियमों के क्रियान्वयन पर सख्त निर्देश

हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश में वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सीईटीपी/ईटीपी की स्थिति, हरित क्षेत्र विकास तथा विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े एजेंडा बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधीर राजपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(पीसीबी) के चेयरमैन जे.गणेशन, सदस्य सचिव योगेश कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने एजेंडा बिंदुओं की समीक्षा करते हुए कहा कि 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल वाली जिन साइट्स पर निर्माण कार्य चल रहा है और जिन्होंने डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, उनके खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर चालान किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जो साइट्स पंजीकृत हैं लेकिन निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहीं, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में एसीएस सुधीर राजपाल ने कहा कि गुरुग्राम में संचालित करीब 400 निर्माण साइट्स पर अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से कवरिंग सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित के खिलाफ चालान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक साइट पर प्रभावी बैरिकेडिंग हो, ताकि शहर में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ गुरुग्राम एक मॉडल शहर के रूप में नजर आए।

पीसीबी के सदस्य सचिव योगेश कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 29 कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि एनसीआर क्षेत्र में 23 नए स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुशासन का लाभ पहुँचाना ही हमारा संकल्प: मनोहर लाल

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज करनाल प्रवास के दौरान ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला के 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सरपंचों व गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अलग-अलग से 3 बैठकें की। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया और पंचायतों की आय के स्त्रोतों को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई । उन्होंने जिन ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए जगह उपलब्ध नहीं है को भी वार्षिक बजट तैयार करने के निर्देश दिए गए।

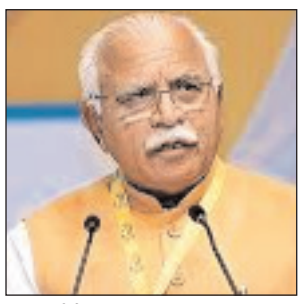

उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार के अलावा सांसद निधि, विधायक निधि तथा सीएसआर फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल सरपंचों व गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ अलग-अलग बैठक करने के उपरांत मीडिया से रूबरू हो रहे थे।

उन्होंने बताया कि विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में गावों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा जो कार्य शुरू नहीं है, उनकी कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि इन 40 गांवों के बाद जिला की सभी 395 ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत -विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी मिलकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना से वंचित न रहे, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुशासन का लाभ पहुंचे, यही हमारा संकल्प है।

हरियाणा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशी विकास पर जोर

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों के समावेशी विकास और सशक्तिकरण को लेकर बेहद संजीदा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बी.एड.और डी.एल.एड. पाठ्यक्रम से निकलने वाला प्रत्येक शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें सहयोग देने और प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस हो। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे समावेशी शिक्षा को मजबूत किया जा सके और भावी शिक्षकों को ऐसे बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

इसी कड़ी में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां राज्य में संचालित विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों और पुनर्वास संस्थानों के कार्य और शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में इस समय 300 से अधिक प्रशिक्षु शिक्षक विशेष शिक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित हैं, जिससे विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और विस्तार मिलेगा। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी.अनुपमा ने बताया कि राज्य के डाइट संस्थानों में शिक्षकों को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम और सीखने से संबंधित कठिनाइयों जैसी विभिन्न स्थितियों की पहचान और हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे पुनर्वास क्षेत्र में राज्य की मानव संसाधन क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों को भी डाइट संस्थानों में खास तौर पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शुरूआती पहचान और हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सुपवा के दीक्षांत समारोह व अभिव्यंजना का पोस्टर लॉन्च, कुलगुरु, रजिस्ट्रार व फैकेल्टी कॉर्डिनेटर रहे मौजूद

सिटी दर्पण संवाददाता

रोहतक

दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) के द्वितीय दीक्षांत समारोह व 11वीं कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का शुक्रवार को पोस्टर लॉन्च किया गया। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलगुरु डॉ अमित आर्य व रजिस्ट्रार डॉ गुंजन मलिक मनोचा ने पोस्टर लॉन्च किया।इस दौरान परीक्षा नियंत्रक डॉ अजय कौशिक, फैकेल्टी कॉर्डिनेटर महेश टीपी, अजय बाहू जोशी, विनय कुमार व डॉ शैली खन्ना भी मौजूद रहे।

सुपवा के कुलगुरु डॉ अमित आर्य ने बताया कि द्वितीय दीक्षांत समारोह 4 मई को यूनिवर्सिटी परिसर में मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल एवं यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रो असीम कुमार घोष डिग्रियां वितरित करेंगे।साल 2014 में अस्तित्व में आने के बाद सुपवा का यह दूसरा दीक्षांत समारोह है, इससे पहले 2021 में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। पांच साल बाद हो रहे इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी कर चुके 760 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां वितरित की जाएंगी। डॉ आर्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान 35 मेधावी छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान फिल्म एंड टेलीविजन फैकेल्टी के 2018 बैच के 42 छात्र-छात्राओं को भी डिग्री प्रदान की जाएंगी। ये वे छात्र हैं, जिनकी डिग्री कोर्स पूरा न होने के कारण अटकी हुई थी।

डॉ आर्य ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा विशिष्ट अतिथि रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वित्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद आदि के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति बारे सहमति प्रदान कर दी है। दीक्षांत समारोह को यादगार बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यूनिवर्सिटी परिसर को विशेष तौर से सजाया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए विभिन्न आयोजन समितियों का गठन कर अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई हैं। आयोजन का हिस्सा बनने के लिए सभी छात्रों व उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है।

रजिस्ट्रार डॉ गुंजन मलिक मनोचा ने बताया कि डीएलसी सुपवा कला एवं सांस्कृतिक शिक्षा देने वाली देश की एकमात्र ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी है, जहां संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला, प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर, डिजाइन, विजुअल आर्ट्स आदि की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। यहां से शिक्षित छात्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुपवा परिवार, प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि छात्रों के परिश्रम और समर्पण का सम्मान करने का मौका भी है।

सुपवा के कुलगुरु डॉ अमित आर्य ने बताया कि कला प्रेमियों के लिए प्रदर्शनी अभिव्यंजना की शुरूआत 3 मई को फैकेल्टी ऑफ डिजाइन परिसर में होगी। यह प्रदर्शनी स्कूल-कॉलेज के छात्रों, कला प्रेमियों व आम लोगों की एंट्री के लिए 5 मई को ओपन की जाएगी, जो 8 मई तक जारी रहेगी। अभिव्यंजना सुपवा के फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की 11वीं सालाना कला प्रदर्शनी है। इसमें विजुअल आर्ट्स के स्नातक व स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के छात्र अपनी साल भर में तैयार की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपनी रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और कलात्मक दृष्टि को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे।उन्होंने बताया कि 3 और 4 मई को सिर्फ अतिथि और निमंत्रण से आने वाले मेहमानों के लिए प्रदर्शनी ओपन रहेगी। आम जनता 5 से 8 मई तक इसका अवलोकन कर सकेगी।

कुलगुरु डॉ अमित आर्य ने बताया कि अभिव्यंजना में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के विभिन्न विभागों एनिमेशन, मल्टीमीडिया, एप्लाइड आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर और प्रिंटमेकिंग के छात्रों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। पारंपरिक व आधुनिक कला शैलियों का यह संगम दर्शकों को विविध अनुभव प्रदान करेगा। डिजिटल आर्ट से लेकर क्लासिकल पेंटिंग और थ्री डायमेंशन स्कल्पचर तक, हर माध्यम की झलक यहां देखने को मिलेगी। डॉ आर्य ने कहा कि कला और विचारों के प्रदर्शन का यह सालाना आयोजन सुपवा की पहचान बन चुका है। अभिव्यंजना न केवल छात्रों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है, बल्कि समाज को समकालीन कला से जोड़ने का भी माध्यम है। प्रदर्शनी में आने वाले कला प्रेमियों को एक समृद्ध और प्रेरणादायक अनुभव मिलेगा, जो कला के प्रति उनकी समझ को और अधिक गहरा करेगा।

संपादकीय

व्यावसायिक एलपीजी रु 3,071 पार, छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ीं

1 मई 2026 का दिन देश के लाखों छोटे व्यवसायियों, रेस्तरां मालिकों, ढाबा चलाने वालों और खाद्य विक्रेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा। केंद्र सरकार ने इसी दिन से 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में रु 993 की भारी वृद्धि लागू कर दी। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत रु 2,078.50 से उछलकर रु 3,071.50 हो गई, जबकि मुंबई में यह रु 2,031 से बढ़कर रु 3,046.50 पर पहुँच गई। कोलकाता में तो स्थिति और भी विकट है – वहाँ एक ही महीने में रु 1,147 की वृद्धि हुई और कीमत रु 3,355 तक जा पहुँची। यह भारतीय इतिहास में व्यावसायिक एलपीजी में की गई अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त वृद्धि है। यह कोई अकेली घटना नहीं है। मार्च 2026 की शुरूआत से अब तक यह चौथी बार है जब व्यावसायिक गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। 1 मार्च को मामूली बढ़ोतरी से शुरू हुआ यह सिलसिला 7 मार्च को रु 114.50, अप्रैल में रु 218 और अब मई में रु 993 की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ एक भयावह रूप ले चुका है। मार्च से मई के बीच दिल्ली में 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत कुल रु 1,331 बढ़ी है – यानी लगभग 48 प्रतिशत की बढ़ोतरी। यह आँकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस मूल्यवृद्धि की मूल जड़ें मध्य-पूर्व में भड़की भू-राजनीतिक अशांति में हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव ने वैश्विक तेल बाजारों में गहरी उथल-पुथल मचा दी है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिये पूरा करते हैं, ऐसे वैश्विक उतार-चढ़ाव की मार से बचना चाहते तो हैं, लेकिन अनिश्चित काल तक इससे बचा नहीं जा सकता। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक एलपीजी उनके कुल नेटवर्क की खपत का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा है, और यही कारण है कि सरकार ने इस श्रेणी में मूल्य समायोजन का विकल्प चुना। सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो यह निर्णय बेहद सोचा-समझा प्रतीत होता है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और घरेलू विमानन ईंधन की दरें भी स्थिर रखी गई हैं। इससे देश के लगभग 33 करोड़ परिवार सीधे तौर पर राहत में हैं। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने भी कहा कि करीब 80 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादों के दाम अपरिवर्तित हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकार वैश्विक दबाव और घरेलू स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इस दृष्टि से सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दृष्टिकोण पूरी तरह सफल हो सकता है ? व्यावसायिक गैस और घरेलू गैस की कीमतों के बीच की यह दीवार वास्तव में उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। जब रेस्तरां, होटल, ढाबे, बेकरी और खाना बनाने वाली इकाइयाँ इतने महंगे ईंधन से खाना बनाएँगी, तो उसका बोझ आखिरकार उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। खाने की थाली महंगी होगी, फूड डिलीवरी के दाम बढ़ेंगे, ढाबों में चाय और रोटी के दाम ऊँचे होंगे। यानी घरेलू सिलेंडर की कीमत भले न बढ़े, लेकिन बाहर खाना खाना महंगा जरूर हो जाएगा। इस मूल्यवृद्धि की सबसे कठोर चोट उन लोगों पर पड़ेगी जो भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं – छोटे दुकानदार, फेरीवाले, सड़क किनारे चाट-पकौड़े बेचने वाले, और छोटे कैटरिंग व्यवसाय। इनके पास न तो बड़े वित्तीय भंडार होते हैं, न ही अचानक लागत बढ़ने पर उसे झेलने की क्षमता। ये लोग पहले से ही कम मुनाफे पर काम कर रहे हैं। अब या तो वे कीमतें बढ़ाएँगे – जिससे ग्राहक घटेंगे – या नुकसान झेलेंगे, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। इस वर्ग की आर्थिक स्थिरता पर इस निर्णय के दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न उठता है। क्या सरकार इन छोटे व्यवसायियों के लिए किसी अल्पकालिक राहत पैकेज या सब्सिडी तंत्र पर विचार कर रही है ? क्या उन्हें किसी प्रकार का संक्रमणकालीन समर्थन मिल सकता है जब तक वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर नहीं हो जाते ? सरकार को इस दिशा में सक्रिय रूप से सोचना चाहिए। वाणिज्यिक एलपीजी पर निर्भर छोटे उद्यमों को सहारा देने के लिए कोई विशेष ऋण सुविधा, ब्याज सहायता या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजना का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा पहलू यह है कि यह संकट हमें एक बड़े सवाल की ओर भी धकेल रहा है – भारत की ऊर्जा निर्भरता का। जब भी मध्य-पूर्व में आग लगती है, हमारे ईंधन की कीमतें भड़कने लगती हैं। यह परनिर्भरता कब तक चलेगी ? सौर ऊर्जा, बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों पर गंभीरता से काम करने का यही सही समय है। यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और अनुदान मिले, तो दीर्घकाल में यह समस्या बहुत हद तक सुलझ सकती है। केवल अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ घरेलू कीमतें बदलते रहना कोई स्थायी नीति नहीं हो सकती। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकार इस तरह के मूल्य निर्णयों में पारदर्शिता बनाए रखे। आम व्यवसायी को यह पहले से पता होना चाहिए कि किस आधार पर और कितने समय में कीमतें बदल सकती हैं। यह अनिश्चितता व्यावसायिक योजनाओं को बाधित करती है और छोटे उद्यमियों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। एक स्पष्ट मूल्य समीक्षा नीति और उसकी पूर्व सूचना तंत्र इस समस्या को कुछ हद तक कम कर सकता है। निष्कर्षतः, व्यावसायिक एलपीजी की यह भारी मूल्यवृद्धि वैश्विक परिस्थितियों की उपज है, और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने का सरकार का इरादा सराहनीय है। लेकिन इस राहत की एक अदृश्य कीमत है – छोटे कारोबारियों पर बोझ और अंततः उपभोक्ताओं की जेब पर असर। ऊर्जा नीति में दूरदर्शिता, वैकल्पिक ईंधन की ओर संक्रमण और प्रभावित वर्गों के लिए सहायता ही इस समस्या का टिकाऊ समाधान है। वरना हर बार जब पश्चिम एशिया में बारूद जलेगा, तो भारत की रसोइयों की आँच तेज होती रहेगी – और आम आदमी की थाली और महंगी होती जाएगी।

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रभावशाली जीत

मृत्युंजय दीक्षित (हि.स)

गुजरात नगर निगम, पंचायत तथा पालिका चुनावों के नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहने का संकेत दे दिया है। भाजपा ने अहमदाबाद, सूरत, बडोदरा, राजकोट समेत सभी 15 नगर निगमों व 34 जिला पंचायत में अपना नियंत्रण बरकरार रखा। जिला पंचायत, नगर पालिका व तहसील पंचायत में 90 प्रतिशत से भी अधिक सीटों पर कमल खिला है। भाजपा ने मोरबी व पोरबंदर मनपा में क्लीन स्वीप किया है। अहमदाबाद में एआईएमआईएम का भी सफाया हो गया और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अभी नए बने नगर निगम नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में भाजपा का कमल खिला।

गुजरात में भाजपा की यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी व गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की जोड़ी का यह पहला चुनाव था। चुनाव परिणामों से भाजपा नेतृत्व को काफी राहत मिली है। इसका एक कारण नयी पीढ़ी का धीरे-धीरे सक्षम होना और स्थानीय चुनावों का नेतृत्व करने का सामर्थ्य जुटा लेना भी है। यदि दूसरी पंक्ति का नेतृत्व चुनावी रणनीति में निपुण होगा तो पार्टी के लिए यह निश्चय ही आश्वस्ति का विषय है।

विगत वर्षों से गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये दोनों दल भाजपा के खिलाफ वातावरण तैयार करने में कुछ हद तक सफल हो रहे हैं किंतु गुजरात की जनता ने एक बार फिर लिख कर दे दिया है कि वहां अभी भाजपा का गढ़ हिलाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व अन्य दलों को बहुत पसीना बहाना होगा। सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी जैसे दलों का सफाया हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वहां अब भी हिन्दुत्व की विचारधारा की जड़ें मजबूत हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता होने के पीछे एक बड़ा कारण उसके सात राज्यसभा सदस्यों का भाजपा में शामिल होना भी रहा।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की अयोध्या और गुजरात की एक सीट पर भाजपा को हराने में सफलता प्राप्त की तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने की बात कहकर कई बार गुजरात का दौरा किया था। राहुल सपा सांसद अवधेश प्रसाद को भी गुजरात लेकर गए और अहंकारपूर्ण शब्दों में कहा कि हमने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के हिंदुत्व की विचारधारा को उनके मुख्य केंद्र में पटखनी दी है, अब गुजरात की बारी है।

गुजरात में मिली इस सफलता पर भाजपा के राज्य नेताओं ने कहा कि यह विकास की राजनीति की जीत है। गुजरात की छवि को खराब करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अपना बोरिया-बिस्तर समेट लेना चाहिए। इन पारिणामों ने साफ कर दिया है कि गुजरात में भाजपा की पकड़ शहरों से लेकर गांवों तक बनी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों राज्य में नैरेटिव की लड़ाई भाजपा से हार गयीं। इन परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भाजपा सतर्क रही तो राज्य में वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव आसानी से निकल लेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और दांपत्य जीवन में प्रेम व तालमेल बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: उच्च शिक्षा से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। आप महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से सोच-विचार करेंगे। भाई-बहनों और रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज आपके मन में कई रचनात्मक और नए विचार जन्म लेंगे। परिवार के लोग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बच्चों के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: अपनी योजनाओं को फिलहाल गुप्त रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। परिवार के सदस्य किसी बात से नाराज हो सकते हैं, इसलिए संतुलित व्यवहार रखें। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। नई तकनीक और विचारों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। व्यापार में नए अवसर और सौदे मिल सकते हैं। समस्याओं के मूल कारणों को समझने में आप सफल रहेंगे। दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित न हों। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आपकी कुछ आदतों के कारण परिवार के सदस्य परेशान हो सकते हैं। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी है। मन में किसी कारण से आंतरिक तनाव रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी। कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। मनोरंजन और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आप अपने लक्ष्यों को लेकर थोड़ा उदासीन महसूस कर सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्या जैसे एसिडिटी परेशान कर सकती है। बातचीत के जरिए आप कई समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। आपके कुछ विचार दूसरों को असहज कर सकते हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आज आपकी मानसिक स्थिति मजबूत और सकारात्मक रहेगी। संपत्ति बेचने से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ेगी। अपने लक्ष्यों पर आप पूरी तरह केंद्रित रहेंगे। काम से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और समय पर कार्य पूरे करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मकर: नए व्यापार को लेकर आप उत्साहित रहेंगे। उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होकर अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी का योग है। विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध विवाह में बदलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है। फिलहाल बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता से आप विरोधियों पर विजय पा सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव बढ़ेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

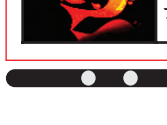

मीन: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। पुरानी समस्याएं फिर से परेशान कर सकती हैं। माता-पिता आपके प्रयासों से खुश रहेंगे। अहंकारी लोगों से दूरी बनाए रखें। किसी पर भी अनावश्यक दबाव डालने से बचें, इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

खाद्य सुरक्षा से खाद्यान्नों के मामले में नेतृत्व की ओरः खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पीएलआई योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव

अविनाश जोशी

खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़

भारत आज अपने आर्थिक सफर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब जबकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है, विकास को सिर्फ उत्पादन की मात्रा से ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सृजित मूल्य के आधार पर भी मापना होगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तुलना में बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहां इस प्रकार का बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है।

भारत खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध और समुद्री उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। दशकों तक, हमारे कृषि संबंधी सामर्थ्य ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर भी, इस उपज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से बेहद ही सीमित मूल्यवर्धन के साथ सीधे खेत से बाजार तक पहुंचता रहा।

आज भारत के कृषि उत्पादन का महज 12-13 प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्करण से गुजरता है। उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच का यही अंतर भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सबसे बड़े अवसरों में से एक है।

इसलिए, खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की यात्रा का अगला चरण बिल्कुल स्पष्ट हैः कृषि की प्रचुर संपदा को उच्च मूल्य वाले एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना।

पीएलआई योजना के पीछे की परिकल्पना

इस अवसर को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2021 में कुल 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की शुरूआत की।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा इस योजना को 2021-22 से 2026-27 तक की छह साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

इस योजना के पीछे का मूल विचार सरल लेकिन ठोस हैः खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग के विस्तार में निवेश करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करना। कुल मिलाकर, यह योजना इन-स्टोर ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में शेल्फ स्पेस और वैश्विक विपणन अभियानों में निवेश करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में खाद्य उत्पादन से जुड़ी वैश्विक स्तर की कई चैंपियन कंपनियां तैयार करती है।

रणनीतिक डिजाइनः एक आधुनिक खाद्य इकोसिस्टम का निर्माण

पीएलआईएसएफपीआई योजना की संरचना को सावधानीपूर्वक को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है।

1. उच्च क्षमता वाले खाद्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना

पहला घटक पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद जैसी प्रमुख खाद्य श्रेणियों में उत्पादन बढ़ाने पर केन्द्रित है।

ये श्रेणियां वैसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत घरेलू खपत और निर्यात क्षमता, दोनों में तेजी से विस्तार कर सकता है।

2. नवाचार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहन देना

दूसरा घटक एमएसएमई द्वारा विकसित नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों को समर्थन प्रदान करता है। लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के खाद्य क्षेत्र की रीढ़ हैं और समावेशी विकास हेतु आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उनका जुड़ाव बेहद जरूरी है।

पोषक अनाज (मिलेट) से संबंधित नवाचारः परंपरा को आधुनिक बाजारों से जोड़ना

वर्ष 2023 में, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष के उपलक्ष्य में, मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत एक विशेष पहल की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पादों में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना था।

मिलेट्स जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, अत्यधिक पौष्टिक और भारत की कृषि परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं।

आधुनिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलेट्स का समावेश कर-के, यह योजना पोषण संबंधी सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि को एक साथ बढ़ावा देती है।

बदलाव से जुड़े आंकड़े

पीएलआई योजना के तहत बहुत ही कम समय में हासिल की गई प्रगति उद्योग जगत की ओर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और इस नीति की प्रभावशीलता को दशार्ती है।

अब तकः

• इस योजना के तहत 165 कंपनियों को मंजूरी दी गई है।

• इनमें से 68 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, साथ ही बड़ी कंपनियों के 40 संविदा निमार्ता भी शामिल हैं।

• कुल मिलाकर 9,207 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।

• प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन की नई प्रसंस्करण और संरक्षण संबंधी क्षमता सृजित की गई है।

• इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.29 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस योजना का मूल लक्ष्य 25 लाख रोजगार सृजित करना था। इस क्षेत्र ने पहले ही इस लक्ष्य का 131 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है।

पीएलआई समर्थित कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री में भी 2019-20 से 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।

(निर्यात में वृद्धि दर 2019-20 से 7.41 प्रतिशत की है)

विभिन्न पीएलआई योजनाओं के बीच एक चमकता सितारा

उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों को कवर करती है। इनमें से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पीएलआई सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक बनकर उभरी है।

कुल पीएलआई सब्सिडी वितरण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8 से 9 प्रतिशत ही होने के बावजूद, इसने तमाम पीएलआई योजनाओं के तहत सृजित किए गए कुल रोजगारों में से लगभग 42 प्रतिशत रोजगार सृजित किए हैं।

अब तक, इस योजना के तहत कुल 2715 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। यह कुल परिव्यय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है।

यह साबित करता है कि खाद्य प्रसंस्करण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में से एक है।

उपभोक्ताओं की बदलती जीवनशैली के अनुरूप बदलाव

भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन का असर खाद्य उद्योग पर भी पड़ रहा है।

युवा और शहरीकरण की ओर अग्रसर आबादी की बढ़ती मांगें इस प्रकार हैंः

• खाद्य संबंधी सुविधाजनक उपाय

• स्वच्छ पैकेजिंग

• सुरक्षित और पौष्टिक खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) उत्पाद

बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में काम करने वाले पेशेवर अक्सर पकाने के लिए तैयार (रेडी-टू-कुक) या खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) वैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन की तलाश में रहते हैं जो उनकी तेज रफ्तार जीवनशैली के अनुरूप हो।

खाद्य सुरक्षा से खाद्य नेतृत्व की ओर

भारत की प्रचुर कृषि संपदा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सामने इस प्रचुर संपदा को सतत आर्थिक मूल्य में बदलने की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इस बदलाव को गति देने में सहायक साबित हो रही है और खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर खाद्यानों के मामले में नेतृत्व का सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।

(लेखक आईएएस अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव हैं)

देवर्षि नारदः देवताओं के दिव्य दूत और संचार के अग्रणी साधक

नारद मुनि की छवि इधर की उधर करने वाले और आपस में भिड़ाकर क्लेश कराने वाले पौराणिक चरित्र के रूप में गढ़ दी गयी है लेकिन वास्तव में उनका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना परिलक्षित होता है। वे एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण करते हुए संवाद-संकलन का कार्य कर सक्रिय एवं सार्थक संवाददाता की भूमिका निभाते हैं। संवाद के माध्यम से वे तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का कार्य करते हैं। देवताओं के ऋषि होने के साथ-साथ उन्हें देवताओं का दिव्य दूत और संचार का अग्रणी साधक माना गया है। उन्हें ब्रह्माण्ड का पहला ऐसा संदेशवाहक माना जाता है, जो एक लोक से दूसरे लोक की परिक्रमा करते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान किया करते थे।

मान्यता है कि देवर्षि नारद का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन हुआ था। प्रतिवर्ष इसी दिन नारद जयंती मनाई जाती है, जो इस वर्ष 2 मई को मनाई जा रही है। इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात देवर्षि नारद की पूजा की जाती है। अपनी वीणा की मधुर तान से भगवान विष्णु का गुणगान करने और अपने श्रीमुख से सदैव नारायण-नारायण का जप करते हुए विचरण करने वाले नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुकदेव का गुरू माना जाता है। कुछ शास्त्रों में नारद मुनि को त्रिकालदर्शी और विष्णु का अवतार भी माना गया है। श्रीमद्भागवद्पुराण के अनुसार सृष्टि में भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है। कुछ स्थानों पर उनका वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है।

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

धार्मिक पुराणों के अनुसार अनेक कलाओं तथा विद्या में निपुण देवर्षि नारद को संगीत की शिक्षा ब्रह्माजी ने स्वयं दी थी और भगवान विष्णु ने उन्हें माया के विविध रूप समझाए थे। मान्यता है कि देवर्षि नारद ने ही भक्त प्रह्लाद, भक्त अम्बरीष, भक्त ध्रुव इत्यादि भगवान विष्णु के कई परम भक्तों को उपदेश देकर उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। उन्होंने ही भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया। देवराज इन्द्र को समझा-बुझाकर देव नर्तकी उर्वशी का पुरुरवा के साथ परिणय सूत्र कराया। इसके अलावा वे कई अत्याचारी महाराक्षसों द्वारा जनता के उत्पीड़न का वृत्तांत भगवान तक पहुंचा कर उनके विनाश का माध्यम भी बने। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि समस्त युगों, कालों, विधाओं और वर्गों में सम्मान के पात्र रहे नारद जी का सभी लोकों की जानकारी रखने वाले मेधावी नीतिज्ञ तथा प्रभावशाली वक्ता के रूप में स्मरण किया जाता है।

जन-जन के हितकारी देवर्षि नारद किस प्रकार धरती पर विभिन्न प्राणियों को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते थे, इसका उल्लेख भी एक पौराणिक कथा में मिलता है। कथानुसार, एक बार देवर्षि नारद ने बैकुंठधाम जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे पृथ्वी पर लोगों को दुखी देखकर खुद बहुत आहत हैं क्योंकि वहां धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का नहीं बल्कि गलत कार्य करने वालों का ही भला होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है, सब नियति के जरिये ही हो रहा है। हालांकि उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या देख लिया, जिसके आधार पर वे ऐसा कह रहे हैं ? तब देवर्षि ने कहा कि उन्होंने जंगल में दलदली जमीन में फंसी एक गाय देखी। एक चोर वहां आया और गाय को दलदल में फंसी देखकर भी उसकी कोई मदद करने के बजाय वह उसी पर चढ़ कर दलदल लांघ कर निकल गया, उसे आगे जाकर सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। कुछ पलों बाद वहां एक वृद्ध साधु आए, जिन्होंने काफी प्रयासों के बाद गाय को दलदल से बाहर निकाल दिया लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वही साधु गहरे गड्ढे में गिरकर घायल हो गए। आखिर यह कौन-सा न्याय है ?

देवर्षि की बातें सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि जो चोर गाय पर चढ़कर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक बड़ा खजाना था लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली जबकि साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी थी लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी-सी चोट में बदल गई। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि किसी भी इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है।सद्ग्रुणों के अथाह भंडार और समस्त शास्त्रों में प्रवीण देवर्षि नारद को शास्त्रों में मन का ऐसा भगवान कहा गया है, जो किसी भी होनी-अनहोनी को समय रहते पहचान लेते हैं।

उन्हें वेदों और उपनिषदों का मर्मज्ञ, न्याय तथा धर्म का तत्वज्ञ, शास्त्रों का प्रकांड विद्वान, इतिहास व पुराण विशेषज्ञ, औषधि ज्ञाता, योगनिष्ठ, ज्योतिष एवं संगीत विशारद, भक्ति रस का प्रमुख तथा अतीत की बातों को जानने वाला माना गया है। वे ऐसे पौराणिक चरित्र हैं, जो तत्वज्ञान में परिपूर्ण हैं। पच्चीस हजार श्लोकों वाला प्रसिद्ध 'नारद पुराण' देवर्षि द्वारा ही रचा गया है, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति महिमा के साथ-साथ मोक्ष, धर्म, संगीत, ब्रह्मज्ञान, प्रायश्चित इत्यादि कई विषयों की मीमांसा प्रस्तुत की है। इसके अलावा संगीत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ 'नारद संहिता' भी है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को मजदूरी में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा: भगवंत मान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मई दिवस के अवसर पर आज पंजाब विधान सभा ने 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के लिए सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बढ़ोतरी को श्रम वर्ग के योगदान के प्रति सम्मान बताया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा ही श्रमिकों की जिंदगी सुधार सकती है और 'आप' की अगुवाई वाली सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार कर रही है। उन्होंने विशेष सत्र से वाकआउट करने के लिए कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा।इस मौके पर उन्होंने एलान किया कि जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान (संशोधन) एक्ट-2026 के पारित होने पर शुक्राना यात्रा निकाली जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, श्रम श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेस दर (मूल दर) आखिरी बार साल 2012 में संशोधित की गई थी। हालांकि साल 2012 से अब तक महंगाई भत्ता बढ़ता रहा है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी की बेस दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मई दिवस के इस पवित्र दिन पर विधान सभा के इस विशेष सत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है।

इस बढ़ोतरी को मजदूरों के योगदान के प्रति सम्मान बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी सही मायनों में श्रमिकों के प्रति सच्चा सम्मान है, जो उनके योगदान की तारीफ करता है। पूरा सदन प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक तरक्की में श्रमिकों की मिसाल भूमिका को याद करता है। हालांकि यह बढ़ोतरी 13 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील रवैये के कारण किसी ने भी यह बढ़ोतरी करने की कोशिश नहीं की। पिछली सरकारों की नाकामी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पिछली दो सरकारों का कार्यकाल इन मेहनतकश लोगों की मजदूरी बढ़ाए बिना ही गुजर गया, जबकि यह वर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी है। विश्व स्तर पर मजदूरों के संघर्ष के प्रतीक माने जाने वाले मई दिवस पर मैं उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने साल 1886 में

- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम वर्ग को तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान
- 13 साल बाद न्यूनतम मजदूरी में हुई बढ़ोतरी, पिछली सरकारें श्रमिकों की पीड़ा समझने में नाकाम रहीं
- सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मजदूरों के बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, 'आप' सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है: मुख्यमंत्री

शिकागो में काम करने की हालत सुधारने के मसले पर अपनी जानें न्योछावर कर दी थीं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि श्रमिक और मजदूर वर्ग को विकास, शांति और खुशहाली के युग की शुरूआत के लिए आगे आना चाहिए और मई दिवस को सिर्फ ऐतिहासिक दिवस के तौर पर ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ प्रण लेकर मनाना चाहिए। सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल उनकी भलाई के लिए की है और रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी के जरिए उनकी भलाई को और मजबूती मिलेगी।

विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्र की शुरूआत सुहृदयता से हुई, लेकिन कांग्रेसी नेता इसे हजम नहीं कर सके और कोई मुद्दा न होने के बहाने इसका बहिष्कार कर दिया, जो बड़े जमींदारों, कारोबारियों और कुलीन वर्गों के रूप में उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, जिन्हें श्रमिकों की भलाई से कोई लेना-देना नहीं।इसके उलट 'आप' सरकार ने मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

शिक्षा सुधारों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव से सरकारी स्कूलों में अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के बच्चे बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और हाल ही में 359 विद्यार्थियों ने जेईई मेन की परीक्षा पास की है। उन्होंने बताया कि अपना अनुभव साझा करने वाले विद्यार्थियों में से 15 में से 9 से 10 बच्चे मजदूरों के थे। उन्होंने आगे कहा कि जब इन बच्चों को अच्छी प्लेसमेंट मिलेंगी, उनके परिवारों की किस्मत अपने-आप बदल जाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब और पिछड़े वर्गों के परिवारों को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। इसी कारण सरकार ने शिक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। मैं मजदूरों के हकों के लिए लड़ने वाली मजदूर यूनियनों और उनके जोश को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी, ताकि वे प्रदेश और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान देते रहें।

कानून का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें वाहिगुरु ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को सर्वसम्मति से पारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस बिल में 'बेअदबी' के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, जो अपराध करने वालों में डर का माहौल पैदा करके ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 'बेअदबी' प्रदेश की शांति, सद्भावना, भाईचारे की साझेदारी और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने की गहरी साजिश थी।

सख्त कार्रवाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि इस अक्षम्य अपराध के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा, जो दूसरों के लिए भी कड़ा सबक होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता समान हैं और उनकी पवित्रता सुनिश्चित करना हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक कदम के लिए खुशी और धन्यवाद जाहिर कर रहे हैं।

यात्रा का एलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए वह 6 मई को श्री आनंदपुर साहिब से शुक्राना यात्रा शुरू करेंगे, जो 9 मई तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेककर शुक्राना किया जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस महत्वपूर्ण एक्ट को पारित करने के लिए सामर्थ्य और हिम्मत देने के लिए अकाल पुरख का धन्यवाद करना है।

पंजाब के मुख्य सचिव ने मिसाल कायम करके नागरिकों से जनगणना 2027 के स्व-गणना अभियान में शामिल होने का आग्रह किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्य सचिव, श्री के ए पी सिन्हा आईएएस, ने अपने आवास पर ऑनलाइन पोर्टल (शीूल्ल२४२.ॅङ्म५.ल्ल) के माध्यम से अपनी स्व-गणना पूरी की। इस प्रक्रिया को श्री मंजीत सिंह ब्रार, प्रशासनिक सचिव, स्थानीय शासन विभाग, और डॉ. नवजोत खोसा, निदेशक, जनगणना संचालन निदेशालय, पंजाब एवं चंडीगढ़, द्वारा सुगम बनाया गया।

उन्होंने राज्य के सभी निवासियों से राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की, इसे एक नागरिक जिम्मेदारी बताते हुए, जो सार्वजनिक आवश्यकताओं का आकलन करने, संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन को सुनिश्चित करने, और सुशासन को मजबूत करने में मदद करती है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि हर परिवार की गणना हो, हर किसी से पहुंच बनाई जाए और कोई भी पीछे न छूटे।

मुख्य सचिव ने कहा कि सक्रिय जनभागीदारी एक अधिक मजबूत, अधिक समावेशी और विकसित भारत के निर्माण में मदद करेगी। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि विश्वसनीय जनगणना डेटा स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों, कल्याणकारी योजनाओं, और विकास नीतियों की योजना का आधार बनता है, जिससे स्व-गणना विकसित भारत के विजन को साकार करने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाती है।

स्व-गणना, जनगणना 2027 की एक प्रमुख विशेषता है और इसे पंजाब राज्य में 30 अप्रैल, 2026 से 14 मई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह व्यक्तियों को अपने घरों में आराम से ऑनलाइन अपने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक विवरण सुविधापूर्वक प्रस्तुत करने में सक्षम बनाती है। इसके महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि एक विश्वसनीय और समावेशी जनगणना के संचालन के लिए स्व-गणना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नागरिकों को अपने परिवार, समुदाय, और क्षेत्र के सटीक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में सीधे योगदान देने का अवसर देती है। यह पहल भौतिक संपर्क की आवश्यकता को उल्लेखनीय रूप से कम करती है, जबकि डेटा संग्रह की दक्षता, कवरेज, और विश्वसनीयता को बढ़ाती है। इसके बाद 15 मई, 2026 से 13 जून, 2026 तक गृह सूचीकरण चरण आयोजित किया जाएगा।

सभी निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और जनगणना 2027 की सफलता में पूरे मन से योगदान दें। उनकी सक्रिय भागीदारी एक व्यापक और विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो सूचित निर्णय-निर्माण और भविष्य की योजना के लिए आवश्यक है।

पंजाब लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का उत्सव मनाया गया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- संत नामदेव जी एवं गुरु गोबिंद सिंह जी का संबंध पंजाब-महाराष्ट्र के ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक : राज्यपाल

पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता कटारिया सहित पंजाब लोक भवन, चंडीगढ़ में महाराष्ट्र, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश (15 अप्रैल) के स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित हुए। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को कुछ कारणोंवश आयोजित न हो पाने के कारण इसे आज महाराष्ट्र एवं गुजरात के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भाषा, संस्कृति, परंपराओं और विरासत के आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा के वीडियो संदेश के प्रदर्शन से हुआ, जिसके पश्चात महाराष्ट्र की विरासत, विकास और उपलब्धियों पर आधारित एक वृत्तचित्र प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर श्री अजीत बालाजी जोशी, आईएएस ने महाराष्ट्र, श्री धर्मेश जिवानी ने गुजरात तथा डॉ. ए.के. अत्री ने हिमाचल प्रदेश पर अपने विचार रखे। तीनों राज्यों की लोक-सांस्कृतिक विरासत पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (ठेउउ), पटियाला द्वारा प्रस्तुत की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश की किन्नौरी नाटी एवं लुड्डी, महाराष्ट्र की सोंगी मुखवटे एवं लावणी तथा गुजरात के डांडिया, राठवा और तलवार रास ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का समापन सभी कलाकारों द्वारा भव्य संयुक्त प्रस्तुति के साथ हुआ। तीनों राज्यों के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल श्री कटारिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों एवं कामगारों को बधाई देते हुए उन्हें राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला बताया। हिमाचल प्रदेश के संबंध में राज्यपाल ने कहा कि यह राज्य साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बागवानी और जलविद्युत के क्षेत्र में अग्रणी प्रगतिशील राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने इसकी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक धरोहर, वीर सैनिकों, हस्तशिल्प, लोकनृत्यों तथा शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वीर भूमि हिमाचल प्रदेश ने देश को मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन सौरभ कालिया जैसे वीर सपूत दिए हैं। महाराष्ट्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसकी समृद्ध सभ्यता, संतों, समाज सुधारकों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान तथा भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मुंबई, यूनेस्को धरोहर स्थलों, किलों, लावणी एवं तमाशा जैसी परंपराओं तथा वड़ा पाव, मिसल पाव और पूरन पोली जैसे व्यंजनों का उल्लेख किया। उन्होंने संत नामदेव जी के माध्यम से महाराष्ट्र और पंजाब के पवित्र संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित है। उन्होंने यह भी कहा कि नांदेड़ एवं तख्त श्री हजूर साहिब से गुरु गोबिंद सिंह जी का संबंध दोनों राज्यों के स्थायी आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। गुजरात के संबंध में राज्यपाल ने उसके गौरवशाली इतिहास, उद्यमशीलता तथा स्वतंत्रता आंदोलन, उद्योग और नवाचार में योगदान की सराहना की। उन्होंने गुजरात को महात्मा गांधी, सरदार पटेल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की धरती बताते हुए श्वेत क्रांति, गिर राष्ट्रीय उद्यान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती आश्रम, बंदरगाहों, औद्योगिक विकास तथा गरबा और डांडिया की समृद्ध परंपराओं का उल्लेख किया।

पंजाब विधान सभा ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2026 किया पारित : संजीव अरोड़ा

चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा ने आज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक-2026 पारित कर दिया। पंजाब में कार्यरत सोसाइटियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू कामकाज को बढ़ाने पर केंद्रित यह विधेयक कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब विधान सभा में प्रस्तुत किया। पंजाब सरकार ने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में 1860 के ऐतिहासिक सोसाइटीज एक्ट में संशोधन करके सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) एक्ट, 2026 पेश किया है। कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह विधेयक नियामक ढांचे, प्रबंधन करने वाली सोसाइटियों, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, समाज कल्याण की गतिविधियों में लगी सोसाइटियों को आधुनिक बनाएगा। ये संशोधन सभी समाजों को एक समान, पारदर्शी शासन के अधीन भी लाते हैं ताकि सार्वजनिक फंडों और कर-मुक्त स्त्रोतों का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में सभी पंजीकृत सोसाइटियां अब सूचना अधिकार (आर.टी.आई.) एक्ट के अधीन आएंगी, जिससे सार्वजनिक जांच, निर्णय लेने में पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रारों को कानून का पालन सुनिश्चित करने और फंडों के दुरुपयोग या बताए गए उद्देश्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए सोसाइटियों से कोई भी जानकारी या रिकॉर्ड मांगने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस विधेयक में, सभी सोसाइटियों को अपने सही रिकॉर्ड, निरंतर कार्यशीलता और समय-समय पर अपने उद्देश्यों एवं प्रबंधन का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद अपना पंजीकरण नवीनीकृत करवाना होगा। पंजाब में मौजूद सभी सोसाइटियों को संशोधित एक्ट के लागू होने के एक वर्ष के भीतर पुनः पंजीकरण करवाना होगा, जिससे उन्हें नए नियमों और पारदर्शी ढांचे के अधीन लाया जा सकेगा।

मजदूर हमारे विकास की नींव, अमन अरोड़ा ने मई दिवस पर मेहनतकशों की मेहनत को किया सलाम

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारत के विकास का श्रेय मेहनतकशों को देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि असली लोकतंत्र अमीरों की दौलत से नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग के सम्मान और खुशहाली से मापा जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की मजदूरों के सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विशेष विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हमें इस पवित्र दिन पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को नमन करना चाहिए क्योंकि यह दिन उन मेहनती मजदूरों की मजदूरी को सलाम करता है, जिन्हें बाबा साहब ने सशक्त बनाकर उनके सम्मान और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा कि देश की हर सड़क, फैक्ट्री, खेत और शहर अपने कामगारों के कंधों पर खड़ा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर देश को भोजन देने तक, उद्योग चलाने से लेकर आवश्यक सेवाओं को संभालने तक, मजदूर सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास की नींव हैं।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वह अपने सुनाम स्थित कार्यालय में सेवा केंद्र चला रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजदूर और आम नागरिक बिना भाग-दौड़ किए अपने काम आसानी से करवा सकें। उन्होंने 2022 के चुनाव अभियान का एक भावुक किस्सा साझा किया। सुनाम हलके के शाहपुर कलां गाँव की यात्रा को याद करते हुए श्री अरोड़ा ने बताया कि उन्हें तेज धूप में मनरेगा के तहत काम करने वाली बुजुर्ग महिलाओं (माइयों) ने रोका था। उन्होंने सदन को बताया कि उनमें से एक बुजुर्ग माता ने मुझे गले लगाया और 100 रुपये का घिसा हुआ नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा कि अमन, मुझे आखिरकार मेरी पहली पेंशन मिल गई। यह 100 रुपये तेरे लिए, मेरा आशीर्वाद है। माता ने आगे कहा कि मुझे अकाली और कांग्रेस के राज में कभी पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन तुम्हारे प्रयासों से यह संभव हुआ।

राजनीति और कारोबार में पैसा आता-जाता रहता है। लेकिन उस माँ के खून-पसीने से कमाए यह 100 रुपये मेरे लिए करोड़ों रुपये से अधिक मायने रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के अनुसार मैंने सुनाम सीट 75,000 से अधिक वोटों से जीती। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि यह उस माँ का आशीर्वाद था जिससे मैं जीता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता को सही ठहराते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि अगर विधायकों की संख्या की बात करें तो इस पक्ष से हमें यह प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे विधायक सदन में एक परिवार की तरह एकजुट होकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल हम यह प्रस्ताव कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा नेताओं को चुप कराने के लिए लाए हैं, जो बेकार की नौटंकी कर रहे थे।

संक्षिप्त-समाचार

पंजाब विधानसभा ने आज पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन ने प्रजा मंडल आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी श्री चमन लाल, प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री रघु राय, भारत-पाक युद्ध में भाग लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल दीपिंदर सिंह तथा हॉकी ओलंपियन सरदार गुरबख्श सिंह ग्रेवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करते समय सम्मान स्वरूप दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन भी रखा गया।

पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा डायरैक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज की स्थापना को हरी झंडी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज जन सुरक्षा को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और नियामक ढांचे को और बेहतर बनाने पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें नई फोरेंसिक विज्ञान प्रणाली, नई फार्म स्टे नीति और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन कानून में संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों की उचित प्रक्रिया और अपराधों की तेजी से जांच के माध्यम से जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने आज डायरैक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया। डायरैक्टोरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज (डी.एफ.एस.) पंजाब, जिसे पहले फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, पंजाब के नाम से जाना जाता था, गृह विभाग के नियंत्रण में होगा। डी.एफ.एस. के अधीन काम करने वाली क्षेत्रीय परीक्षण फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को अब क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के रूप में जाना जाएगा, जबकि मुख्य रसायन जांच प्रयोगशाला, खरड़ को डी.एफ.एस. में विशेष टौकसीकोलौजी डिवीजन के रूप में शामिल किया जाएगा। अमृतसर, बठिंडा और लुधियाना में काम कर रही क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशालाओं में डी.एन.ए., बैलिस्टिक्स, साइबर फोरेंसिक्स, दस्तावेज और भौतिकी/ऑडियो वॉयस सहित नए तकनीकी डिवीजनों के सृजन के माध्यम से फोरेंसिक क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही 28 मोबाइल फोरेंसिक यूनिटें स्थापित की जाएंगी, जिसमें प्रत्येक पुलिस जिले में एक साइंटिफिक अधिकारी (क्राइम सीन) की निगरानी में एक मोबाइल फोरेंसिक वैन काम करेगी।

विधानसभा के ऐतिहासिक सत्र के दौरान मजदूरों की मजदूरी में संशोधन और वृद्धि संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पारित

चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रम मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज पंजाब विधानसभा में पूरे राज्य के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन और वृद्धि संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव 'श्रमिक दिवस' (मजदूर दिवस) के अवसर पर बुलाए गए विधानसभा के एक विशेष और ऐतिहासिक सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया। मंत्री ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बेसिक दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया। प्रस्ताव पेश करते हुए श्रम मंत्री ने बताया कि देश, समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले मजदूरों के बहुमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए लगभग 69 वर्षों के बाद 1 मई को ऐसा ऐतिहासिक सत्र बुलाया गया है।

केंद्रीय मंत्री श्री जे. पी. नड्डा का नाईपर, मोहाली में दौरा

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ने शुक्रवार, 01 मई 2026 को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईप), मोहाली का दौरा किया। माननीय मंत्री नाईपर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां उनके साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग , भारत सरकार से सचिव श्री मनोज जोशी, अवर सचिव सुश्री गीता अशोक एवं उप सचिव डॉ. किन्नी सिंह भी उपस्थित रहे।

इसके बाद बोर्ड रूम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नाईपर, मोहाली के निदेशक प्रो. दुलाल पांडा ने संस्थान की दृष्टि, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (ङ्ढक) तथा स्ट्रेटेजिक रोडमैप प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में उत्कृष्टता केंद्रों जैसे उडए-अश्अइ एवं उ ड ए - बायोफार्मास्यूटिकल्स, संस्थान के नवाचार तंत्र तथा लाइसेंसिंग अवसरों पर विशेष प्रकाश डाला गया। प्रो. पांडा ने बताया कि नाईपर, मोहाली शोध उत्कृष्टता के लिए समर्पित है, जिसने उत्कृष्ट एलुमनाई तैयार किए हैं और नाईपर, मोहाली राष्ट्रीय विकास में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान भारत सरकार के बायोफार्मा शक्ति मिशन को सुदृढ़ करने के लिए सेल एवं जीन थेरेपी, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, चिकित्सा उपकरण, एआई आधारित फामाकोइन्फॉर्मेटिक्स तथा उन्नत औषधि वितरण प्रणालियों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस दिशा में संस्थान ने बायोफार्मास्यूटिकल्स और रेगुलेटरी अफेयर्स में दो नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं।

सचिव श्री मनोज जोशी ने संकाय एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उद्योग सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया तथा एक्सटर्नल फंडिंग प्राप्त करने वाले संकाय के लिए प्रोत्साहन एवं उद्योग-प्रायोजित अनुसंधान बढ़ाने की बात कही। उन्होंने पेपर पेटेंट से आगे बढ़कर वास्तविक अनुप्रयोग एवं कमर्शियलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।अपने संबोधन में माननीय मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, विशेष रूप से एपीआई, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, सिंथेसिस इंटरमीडिएट्स एवं बायोलॉजिक्स में। उन्होंने नाईपर, मोहाली में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा संस्थान द्वारा उद्योग जगत के लिए तैयार पेशेवरों की सराहना की। अंत में उन्होंने नवाचार एवं इनोवेशन को गति देने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता एवं नीतिगत सुधारों का आश्वासन दिया।

इसके उपरांत, दोपहर कन्वेंशन सेंटर के फोयर में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां माननीय मंत्री जी ने ट्रांसलेशनल रिसर्च के परिणामों को दशार्ते पोस्टर एवं प्रोटोटाइप का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में नाईपर द्वारा किए जा रहे उद्योग सहयोग, पेटेंट तथा क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित पहलु प्रदर्शित किये गए । माननीय मंत्री ने नाईपर, मोहाली के औषधीय रसीले पौधों (टीूल्लिं' र४ू४'ल्ल३२) गार्डन का उद्घाटन भी किया तथा इसके पश्चात संस्थान की अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का दौरा किया, जहां उन्होंने विद्यार्थियों एवं शोधकताओं से संवाद भी किया। यह दौरा भारत सरकार की औषधि शिक्षा को सुदृढ़ करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने की सतत प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

अमेरिका ने ईरान से मांगी परमाणु हथियार न रखने की गारंटी, बदले में किया शांति लौटाने का वादा

तेहरान के बीच नई डील की सुगबुगाहट, क्षेत्र में स्थिरता के लिए अमेरिका ने रखा बड़ा प्रस्ताव

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के मध्य बढ़े हुए तनाव के बीच गुरुवार को कहा कि अगर ईरान को शांति चाहिए तो उसे कभी भी परमाणु हथियार न रखने की गारंटी देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका आज ईरान छोड़ दे, तब भी उसे फिर से खड़ा होने में 20 साल लग का समय लग जाएगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से दावा किया कि ईरान में युद्ध अमेरिका पहले ही जीत चुका है। मगर यह जीत बहुत छोटी है। अमेरिका को और बड़ी जीत चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना के साथ उसका नेतृत्व भी तबाह हो चुका है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर हम अभी वहां से हट जाएं तो उन्हें फिर से सब कुछ खड़ा करने में 20 साल लग जाएंगे। इसमें शक है कि वह ऐसा कर पाएंगे। अमेरिका अभी और बहुत कुछ करना चाहता है। ट्रंप ने कहा, ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि उसके पास कभी भी कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने फिर दृढ़ता से कहा कि ईरान समझौता करने के लिए तत्काल तैयार है। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ईरान के साथ बातचीत रुक गई है। ट्रंप ने कहा, मेरे और कुछ अन्य लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि बातचीत किस मोड़ पर है। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका को हर हाल में ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म होने के साथ गैस की कीमतें तेजी से नीचे गिर जाएंगी। उधर, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की करेंसी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि इस समय ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बेहद नाजुक मोड़ पर है। युद्ध की आशंका के बीच शांति के प्रयास भी जारी हैं। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के सामने सशर्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने और परमाणु वार्ता को फिलहाल टालने की बात कही गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ शुरू किए समन्वित सैन्य अभियान का असर समूचे मध्य पूर्व पर पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव पर संदेह जताया है। वह परमाणु संवर्धन के मुद्दे को दरकिनार किए जाने से नाखुश हैं। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस जलमार्ग को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने इसे व्यापार के लिए बंद करने की धमकी दी है। वह कथित तौर पर सुरंग बिछा रहा है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि ईरान ने भारतीय जहाजों के वहां से गुजरने पर रोक नहीं लगाने का आश्वासन दिया है। इस सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संघर्ष में शांति दूत की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ईरान रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक चक्रव्यूह रचने का प्रयास भी कर चुका है। ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर भी राय बंटी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के कुछ सदस्य सैन्य कार्रवाई के पक्ष में तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई डेमोक्रेट्स संसाधनों की बबार्दी और संभावित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस संघर्ष में अब तक लगभग 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है।

एजीआर मामले में वोडा आइडिया को 23,649 करोड़ की बड़ी राहत

- बकाया चुकाने की अवधि में भी मिली छूट

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने कंपनी को एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू (एजीआर) बकाया के मामले में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने बकाया को चुकाने की अवधि के मामले में भी कंपनी को बड़ी राहत दी है। कंपनी इस बकाया को 2032 से लेकर 2041 तक चुका सकती है। इसका मतलब कंपनी के लिए अगले कुछ वर्षों तक एकमुश्त बड़ी राशि इकट्ठा कर चुकाने की बाध्यता भी खत्म हो गई है।

वोडा आइडिया द्वारा एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई इस जानकारी के अनुसार टेलीकम्युनिकेशन डिपार्मेंट (डीओटी) ने दिसंबर 2025 तक के लिए कंपनी की एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू बकाए की राशि 64,046 करोड़ रुपये निर्धारित कर दी है। इसके पहले के अनुमान में बकाए का आंकड़ा 87,695 करोड़ रुपये का था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्मेंट द्वारा किए गए इस बदलाव से वोडा आइडिया को 23,649 करोड़ रुपये की राहत मिली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार से मिली इस राहत का असर कंपनी के शेयर की चाल पर भी सकारात्मक रूप से पड़ सकता है। आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर स्टॉक मार्केट में छुट्टी है, लेकिन सोमवार को बाजार खुलने पर कंपनी के शेयर की चाल में तेजी आ सकती है। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को वोडा आइडिया के शेयर बीएसई पर 0.68 प्रतिशत लुढ़क कर 10.22 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार वोडा आइडिया को एजीआर बकाये को चुकाने की अवधि में राहत दी गई है। अब वोडा आइडिया से इस बकाये को तुरंत चुकाने की बाध्यता हटा दी गई है। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बकाये को चुकाने का जो प्लान दिया है, उसके अनुसार अब कंपनी को वित्त वर्ष 2031-32 से अगले चार साल तक हर साल बकाये की कम से कम 100 करोड़ रुपये की राशि चुकानी होगी।

इसके बाद शेष बचे बकाये को वित्त वर्ष 2035-36 से वित्त वर्ष 2040-41 तक चुकाने के लिए समान राशि की छह वार्षिक किश्तों में बांट दिया जाएगा। मतलब पहले पांच साल तक तो कंपनी को बकाये के रूप में एक भी पैसा जुटाने की बाध्यता नहीं रहेगी, वहीं अगले पांच साल तक कंपनी के सामने न्यूनतम 100 करोड़ रुपये जुटाने की ही बाध्यता होगी। दस साल की राहत बाद ही वोडा आइडिया को बकाया चुकाने के लिए बड़ी राशि का इंतजाम करना पड़ेगा।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एडजेस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू (एजीआर) बकाये को चुकाने के लिए तैयार किए गए इस प्लान से पहले से ही वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही वोडा आइडिया को बड़ी राहत मिली है।

यूएई ने अपने नागरिकों के ईरान लेबनान इराक जाने पर रोक लगाई

एजेंसी (हि.स.)
अबू धाबी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक जाने पर रोक लगा दी है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि वह क्षेत्र में मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए अपने नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक जाने पर रोक लगा रहा है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन देशों में मौजूद अपने सभी नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे जितनी जल्दी हो वहां से निकलें और सीधे संयुक्त अरब अमीरात लौट आएं। उधर, इस समय अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के कारण संयुक्त अरब अमीरात भारी आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रभावित होने से यूएई का तेल निर्यात बाधित हुआ। अमेरिका और खाड़ी देशों से पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण यूएई ने अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हुए 60 साल पुराना ओपेक संगठन छोड़ दिया है। ईरान ने यूएई के तेल प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है।

खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका से पर्याप्त सैन्य-राजनीतिक समर्थन न मिलने के कारण यूएई ने इस रुख की खुलकर आलोचना की। इससे खाड़ी देशों के पारंपरिक गठबंधन में दरार आ गई है। युद्ध और हमलों के डर से विदेशी पर्यटकों और प्रवासियों ने यूएई (विशेष रूप से दुबई) से दूरी बना ली है। अपनी सुरक्षा और नुकसान की भरपाई के लिए यूएई ने अमेरिका से वित्तीय गारंटी की मांग की है।

राजगढ़ में बाइक पेड़ से टकराई, दो की मौत

राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ब्यावरा थाना क्षेत्र के ग्राम ढकोरा जोड़ के पास गुरुवार की रात एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों रिश्तेदारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, बीती रात ग्राम ढकोरा जोड़ के समीप अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार हरीप्रसाद (35) पुत्र कन्हैयालाल लोधा, निवासी गांगाहोनी थाना सुठालिया, और नरेश (25) पुत्र लालचंद लोधा, निवासी तलावड़ामहाराजा थाना मलावर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि दोनों ब्यावरा से अपने गांव लौट रहे थे, इसी दौरान ढकोरा जोड़ के समीप उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल ब्यावरा भेजा। दोनों मृतक आपस में रिश्तेदार बताए गए हैं और दोनों के दो-दो छोटे बच्चे भी है।

कोलकाता के एक स्ट्रॉन्ग रूम में तृणमूल का हंगामा चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के आरोपों को खारिज किया

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

दक्षिण कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में कथित संदिग्ध गतिविधियों के विरोध में गुरुवार शाम तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चुनाव आयोग ने रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।

तृणमूल उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में विजय उपाध्याय भी विरोध में शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में अंदर कुछ होता दिख रहा है। बैलेट पेपर इधर-उधर किए जा रहे हैं, जबकि अधिकारी कह रहे हैं कि अंदर कुछ नहीं हो रहा। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा उम्मीदवार तापस राय और संतोष पाठक भी पहुंच गए। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की और वहां से लौट गए। रात में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट किया कि स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सील और सुरक्षित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने बताया कि वहां कई केंद्रों की ईवीएम रखी गई हैं और गुरुवार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट को अलग कर रहे थे। इसकी पूर्व सूचना उम्मीदवारों को दी गई थी। मनोज अग्रवाल ने कहा कि पोस्टल बैलेट अलग करने की प्रक्रिया के वीडियो को देखकर ही छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी तरह झूठे और निराधार हैं। स्ट्रॉन्ग रूम 100 प्रतिशत सुरक्षित है। उन्होंने रोप लगाया कि बेवजह माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी भी शाम ढलने के बाद सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीईओ ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को वहां जाने का अधिकार है और इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है।

संक्षिप्त-समाचार

डायन बताकर हत्या के मामले में 8 को आजीवन कारावास

नवादा। नवादा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार खेतान ने डायन बता कर हत्याकांड को अंजाम देने के मामले का निपटारा करते हुए 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों को पांच -पांच हजार रुपये की अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई। न्यायालय सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2019 को नवादा जिले के गोविंदपुर थाना के कोयलियागढ़ गांव में मरनी देवी नामक महिला की डायन बता कर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। महिला को बाल काटकर गांव में भी नग्न करके घुमाया गया था। सिविल कोर्ट में कार्यरत वरीय अपर लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद शर्मा की धारदार साक्ष्यपूर्ण बहस को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश आशुतोष कुमार खेतान ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा है कि डायन बता कर पिटाई कर हत्या करना एक बहुत बड़े सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देना है। जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तो समझ में अराजक माहौल पैदा हो जाएगा। गवाहों के बयानातो तथा पुलिस रिपोर्ट से मिले ठोस सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने नरेश मांझी, बिरजू मांझी, कारु मांझी, तुलसी मांझी, त्रिलोकी मांझी, पूना मांझी, राजेश मांझी तथा सुरेश मांझी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों को पांच -पांच हजार रुपए हत्याकांड के विरुद्ध तथा दो - दो हजार रुपये डायन अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्री शर्मा ने ठोस सबूत प्रस्तुत किया। जिसकी काफी तारीफ की जा रही है।

मणिपुर में सुरक्षाबलों ने पिस्तौल व गोला-बारूद के साथ आरोपित को किया गिरफ्तार

सेनापति (मणिपुर)। मणिपुर के सेनापति जिले में सुरक्षाबलों ने एक अभियान के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एस चाख्रो के रूप में हुई है, जो सेनापति थाना क्षेत्र के माखन सेंटर गांव का निवासी है। पुलिस प्रवक्ता ने आज बताया कि यह गिरफ्तारी 30 अप्रैल को चलाए गए अभियान के दौरान की गई। सुरक्षाबलों ने उसके पास से एक 7.65 मिमी पिस्तौल मैगजीन सहित, 7.65 मिमी के दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया है। मामले की आगे की जांच जारी है, ताकि हथियार के स्रोत और आरोपी के संभावित संबंधों का पता लगाया जा सके।

एसडीपीओ हत्या मामले में मुख्य आरोपित गिरफ्तार

गुवाहाटी। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में वर्ष 2023 में हुए सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (एसडीपीओ) चिंगथम आनंद कुमार सिंह की हत्या मामले में एक मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। एनआईए की ओर से आज जारी बयान के अनुसार, आरोपित ओत्खोथांग बाईटे, जो मणिपुर के तेंगनौपाल जिले के मोरेह का निवासी है, संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 को एक खेल मैदान में जिला पुलिस टीम पर किए गए हमले की साजिश में शामिल था। यह घटना राज्य में जातीय हिंसा के चरम के दौरान हुई थी। हमले के दौरान उग्रवादियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की, जिसमें एसडीपीओ सिंह के पेट में गोली लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले को पहले मोरेह पुलिस ने दर्ज किया था, जिसे मार्च 2024 में एनआईए ने अपने हाथ में लिया। जांच के दौरान एनआईए को पता चला कि इस हमले की साजिश मणिपुर में आतंक फैलाने के उद्देश्य से रची गई थी। इस महीने की शुरूआत में एनआईए ने इस मामले में एक अन्य आरोपी कामगिनथांग गांगटे को भी गिरफ्तार किया था। मामले (आरसी-02/2024/एनआईए/आईएमपी) की जांच जारी है।

धारचूला से आदि कैलाश यात्रा शुरू, पहल दल रवाना

धारचूला। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला से शुक्रवार को ह्यआदि कैलाश यात्रा 2026ह्ल का विधिवत शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। शुक्रवार को धारचूला के उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रियों के दल को रवाना किया। अधिकारियों के अनुसार यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए कुल 500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 350 इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है और प्रशासन द्वारा सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करें। उच्च हिमालयी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को यथासंभव छोटे वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्रशासन के अनुसार यात्रा मार्ग पूरी तरह सुचारू है और सड़क मार्ग खोल दिया गया है। मार्गों के रख-रखाव एवं संचालन के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को सक्रिय कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां अलर्ट मोड में कार्य कर रही हैं और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। यात्रा से पूर्व आईएलपी परमिट, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और मौसम से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

सड़क पर खड़े डंपर से टकराई कार, चालक की हालत गंभीर

हुगली। हुगली जिले के गोघाट के रघुबाती मोड़ इलाके में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सड़क किनारे एक डंपर खड़ा था। उसी दौरान आरामबाग की ओर से आ रही एक चारपहिया गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और खड़े डंपर के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर गोघाट थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को तुरंत कामारपुकुर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

नेपाल में संपत्ति जांच आयोग का दायरा तय

- राष्ट्रपति और मौजूदा जजों को रखा गया इससे बाहर

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल सरकार ने प्रधानमंत्री से लेकर उपसचिव स्तर या उसके समान सार्वजनिक पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की व्यवस्था करते हुए संपत्ति जांच आयोग को कार्यादेश (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) सौंप दिया। दो सप्ताह पहले गठित इस आयोग का कार्यादेश गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसी के साथ आयोग के औपचारिक रूप से काम शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।

कार्यादेश के अनुसार, वर्तमान न्यायाधीशों और नेपाली सेना के पदाधिकारियों के खिलाफ आयोग सीधे जांच नहीं कर पाएगा। जांच के दायरे में आने वालों की सूची में वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, लेकिन उनके सचिवालयों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कार्यादेश में कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर रहे या सेवानिवृत्त हो चुके पदाधिकारी और उनके परिवार के नाम पर देश और विदेश में मौजूद संपत्तियों का विवरण एकत्र कर उसकी जांच की जाएगी। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग में पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश लम्साल सदस्य हैं। आयोग को देश में लोकतंत्र पुनर्स्थापना के बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर सहायक मंत्री तक और संविधान सभा सदस्य सहित सभी सांसदों की संपत्ति की जांच का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक निकायों के पूर्व प्रमुख, पूर्व न्यायाधीश और सहसचिव स्तर के सेवानिवृत्त नेपाली सेना अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, महान्यायाधिवक्ता से लेकर प्रदेश स्तर पर राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति पाने वाले अधिकारी भी जांच के दायरे में होंगे। इसी तरह स्थानीय तह के प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी भी जांच के अधीन होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके सलाहकार, निजी सचिव और अन्य सहयोगी पदाधिकारी जांच के दायरे में आएंगे। चाहे वे राज्यकोष से सुविधा लेते हों या नहीं–दोनों प्रकार के अधिकारियों की जांच होगी। राजपत्र के अनुसार, सहसचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सभी उच्च पदाधिकारी जांच के दायरे में होंगे। सिविल सेवा, पुलिस सेवा, सशस्त्र पुलिस सेवा, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य सेवाओं के अधिकारी भी जांच के दायरे में शामिल होंगे।

विदेश स्थित नेपाली दूतावासों और कूटनीतिक नियोगों के प्रमुख और कर्मचारी भी जांच के अधीन होंगे। यदि किसी उपसचिव स्तर के अधिकारी ने कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य किया है, तो वह भी जांच में शामिल होगा। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर से लेकर सहसचिव स्तर तक के कर्मचारी, सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के उच्च अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे।

लोअर सियांग पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान तेज, पांच गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
लोअर सियांग (अरुणाचल)

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जिले में हाल ही में नए पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक की तैनाती के बाद लिकाबाली चेक गेट पर सघन जांच और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इन चलाए गए लक्षित अभियानों के तहत पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार मामले दर्ज किए हैं, जो मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को दर्शाता है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि इसी क्रम में लिकाबाली चेक गेट पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया। उसकी पहचान लेपराड़ा जिले के न्यिगाम गांव निवासी सेम्मार बसर के रूप में हुई। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से संदिग्ध हेरोइन और गांजा बरामद किया गया। जब्ती के बाद लिकाबाली थाने में मामला संख्या 14/2026 दर्ज किया गया, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(ए) और 20(बी)(ii)(ए) के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, पिछले एक महीने में अलग-अलग अभियानों के दौरान कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 12.64 ग्राम संदिग्ध हेरोइन तथा 106 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। नशा विरोधी अभियान के साथ-साथ पुलिस ने इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जांच अभियान को भी तेज किया है। इस अभियान के तहत लिकाबाली और नारी थाना क्षेत्रों में बीईएफआर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 15 गैर-एफआईआर मामले दर्ज किए गए हैं।

बिहार में भारत-नेपाल सीमा के रक्सौल से 12 हजार प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद

एजेंसी (हि.स.)
रक्सौल (भारत-नेपाल सीमा)

बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल सीमा पर आंध्र प्रदेश नंबर वाली एक संदिग्ध कार से 12 हजार नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। जिनमें नर्फिन, फेनारगन और डाइजापाम जैसी प्रतिबंधित दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं मुख्य रूप से नशे के लिए इस्तेमाल होती है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आंध्र प्रदेश से आई एक कार में बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन नेपाल ले जाए जा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रक्सौल थाना पुलिस ने महदेवा क्षेत्र में घेराबंदी कर दी। संदिग्ध वाहन को रोककर गहन तलाशी ली गई, जिसमें नशीली इंजेक्शन मिल।

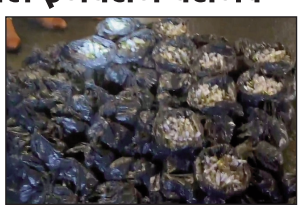

थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान वकील महतो, निवासी कलैया जिला बारा (नेपाल) और पूरन ठाकुर, निवासी बीरगंज जिला परसा (नेपाल) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी लंबे समय से भारत-नेपाल सीमा का फायदा उठाकर नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे की पूछताछ में उनके अन्य साथियों और सप्लायर्स का पता लगा रही है। यह कारोबार लंबे समय से फल-फूल रहा था। गिरफ्तार दोनों तस्करों ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है। दोनों अंतरराष्ट्रीय तस्कर भारत-नेपाल सीमा का फायदा उठाकर नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे।

महंगाई

मई के पहले ही दिन ओएमसी का फैसला

महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर

- घरेलू रसोई गैस की कीमतों में बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। हालांकि ये बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर यानी 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर में ही की गई है। आज सुबह से कमर्शियल सिलेंडर के भाव में लगभग एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राहत की बात है कि आज की इस बढ़ोतरी से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर को बाहर रखा गया है। अब कमर्शियल सिलेंडर देश की राजधानी दिल्ली में 993 रुपये, मुंबई में 993 रुपये, चेन्नई में 990.50 रुपये और कोलकाता में 994 रुपये महंगा हो गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के अनुसार, आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में की गई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2,078.50 रुपये से बढ़ कर 3,071.50 रुपये हो गई है। इसी तरह कोलकाता में इसकी कीमत 2,208 रुपये से बढ़ कर अब 3,202 रुपये हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2,031 रुपये की जगह 3,024 रुपये में मिलेगा, जबकि चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,246.50 रुपये से बढ़ा कर 3,237 रुपये कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भाव पिछले पांच महीनों में छठी बार बढ़े हैं। इससे पहले एक अप्रैल को ये 218 रुपये तक महंगा हुआ था। वहीं मार्च में इसकी कीमत में दो बार बढ़ोतरी की गई। एक मार्च को इसकी कीमत 28 रुपये तक बढ़ी थी, जबकि सात मार्च को यह 114.5 रुपये महंगा हुआ था। इसी तरह फरवरी में इसके दाम में 49 रुपये और जनवरी में 111 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि दिसंबर 2025 में 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी।

राहत की बात ये है कि घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सात मार्च 2026 को 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। आईओसी के अनुसार बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत वर्तमान में दिल्ली में 913 रुपये है। मुंबई में इसकी कीमत 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए आज से ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है।

दूसरे आईएसएसएफ विश्व कप में भाग लेगी भारत की 12 सदस्यीय टीम

भारतीय निशानेबाजों के लिए ओलंपिक की राह और हुई पुख्ता

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय निशानेबाजी दल इस साल के अपने दूसरे बड़े अंतरराष्ट्रीय इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। कजाकिस्तान के खूबसूरत शहर अल्माटी में आयोजित होने वाले आईएसएसएफ (करत्र्क) शॉटगन विश्व कप के लिए भारत ने अपनी 12 सदस्यीय मजबूत टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय दल शनिवार को आयोजन स्थल पर पहुंच जाएगा, जहां वे अभ्यास सत्र के जरिए वहां की परिस्थितियों और हवा के रुख को समझने की कोशिश करेंगे।

यह प्रतियोगिता न केवल पदकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी वैश्विक आयोजनों के लिए रैंकिंग अंक और आत्मविश्वास जुटाने के लिहाज से भी भारतीय निशानेबाजों के लिए सुनहरा अवसर है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में दुनिया भर के दिग्गज निशानेबाज अपनी सटीक निशानेबाजी का लोहा मनवाएंगे।

कजाकिस्तान में 42 देशों के बीच मचेगा घमासान

अल्माटी में होने वाला यह विश्व कप इस साल का दूसरा शॉटगन विश्व कप है। इससे पहले मार्च में मोरक्को के तांजियर में सीजन का पहला चरण आयोजित किया गया था। इस बार प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहने वाला है क्योंकि इसमें 42 अलग-अलग देशों के 284 शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारतीय टीम के लिए यह राह आसान नहीं होगी क्योंकि उन्हें इटली, फिनलैंड, डेनमार्क, चेक गणराज्य, साइप्रस और कतर जैसे देशों के विश्व स्तर के निशानेबाजों से कड़ी

टक्कर मिलने वाली है। खासकर इटली और फिनलैंड की टीमें शॉटगन स्पधाओं में पारंपरिक रूप से काफी मजबूत मानी जाती हैं। भारतीय टीम में 12 मुख्य सदस्यों के अलावा 8 अन्य निशानेबाजों को भी शामिल किया गया है, जो 'आरपीओ' (केवल रैंकिंग अंक के लिए) श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका उद्देश्य युवा निशानेबाजों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना और उनकी वैश्विक रैंकिंग में सुधार करना है। भारत के लिए सबसे बड़ी उम्मीद तीन ओलंपिक कोटा धारक और अनुभवी खिलाड़ी हैं। पुरुष स्कीट स्पर्धा में दो बार के ओलंपियन मैराज अहमद खान और उभरते हुए सितारे अनंतजीत सिंह नारुका अपनी बंदूक से सटीक निशाना लगाएंगे। वहीं, महिला स्कीट स्पर्धा में युवा सनसनी रायजा ढिल्लों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये तीनों खिलाड़ी इस साल पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर उतर रहे हैं, जिससे उनकी फिटनेस और लय का भी परीक्षण होगा। निशानेबाजी के जानकारों का मानना है कि अल्माटी की शूटिंग रेंज अपनी बदलती हवाओं के लिए जानी जाती है, जो स्कीट और ट्रैप जैसे आउटडोर स्पधाओं में बड़ी बाधा बन सकती है।

शेड्यूल और भारतीय दिग्गजों की भागीदारी

प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज सोमवार, 4 मई को पुरुषों और महिलाओं के 'स्कीट क्वालीफायर' के साथ होगा। भारत की नजरें शुरुआती दिनों में ही पदक तालिका में जगह बनाने पर होंगी।

- 5 मईः पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिगत स्कीट स्पर्धा के फाइनल खेले जाएंगे।
- 9 मईः ट्रैप स्पर्धा के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे।
- 10 मईः शनिवार को ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा के साथ प्रतियोगिता का समापन होगा।

मेलबर्न रेनेगेड्स को बड़ा झटकाः कोच साइमन हेलमोट ने पांच साल बाद छोड़ा पद

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

फोटोः हि.स.

मेलबर्न रेनेगेड्स के मुख्य कोच साइमन हेलमोट ने पांच साल के कार्यकाल के बाद क्लब छोड़ने का फैसला किया है। 54 वर्षीय हेलमोट अब नए अवसरों की तलाश करेंगे।

हेलमोट ने 2021 में टीम की कमान संभाली थी और अपने पहले ही सीजन में टीम को उपविजेता बनाया। हालांकि, उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) के 10वें सत्र में टीम को पहला खिताब दिलाना रही। इस ऐतिहासिक जीत में कप्तान सोफी मोलिन्यू के साथ उनकी रणनीति ने अहम भूमिका निभाई।

वर्तमान में हेलमोट भारत में सनराइजर्स हैदराबाद के सहायक कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां वह मुख्य कोच डेनियल विटोरी और कप्तान पैट कमिंस के साथ जुड़े हुए हैं।

हेलमोट का रेनेगेड्स से जुड़ाव बिग बैश लीग की शुरूआत से रहा है। वह पुरुष टीम के पहले कोच भी रहे और चार वर्षों तक इस भूमिका में रहे।

हेलमोट के कार्यकाल में टीम का प्रदर्शन

डब्ल्यूबीबीएल 07:	उपविजेता
डब्ल्यूबीबीएल 08:	7वां स्थान
डब्ल्यूबीबीएल 09:	8वां स्थान
डब्ल्यूबीबीएल 10:	चैंपियन
डब्ल्यूबीबीएल 11:	5वां स्थान

क्लब ने जताया आभार

रेनेगेड्स के महाप्रबंधक जेम्स रोसेनगार्टन ने कहा कि हेलमोट ने क्लब को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मैदान के साथ-साथ टीम के माहौल पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, स्टाफ और प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा याद रखा जाएगा। हेलमोट के जाने के बाद बिग बैश लीग में कोच पदों की खाली जगहों की संख्या बढ़ गई है। इससे पहले सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स की पुरुष टीमों के मुख्य कोच पद भी खाली हैं।

फीफा विश्व कप 2026 के बाद संन्यास लेंगे मेक्सिको के दिग्गज गोलकीपर गिलर्मो ओचोआ

एजेंसी (हि.स.)
मेक्सिको सिटी

मेक्सिको के अनुभवी गोलकीपर गिलर्मो ओचोआ ने घोषणा की है कि वह फीफा विश्व कप 2026 के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह टूर्नामेंट उनके पेशेवर करियर का भी अंतिम पड़ाव हो सकता है। विश्व कप के दौरान 41 वर्ष के होने वाले ओचोआ अब तक पांच विश्व कप खेल चुके हैं और छठे विश्व कप के लिए भी उनके चयन की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

साइप्रस क्लब एईएल लिमासोल के लिए खेल रहे ओचोआ ने एक साक्षात्कार में कहा कि राष्ट्रीय टीम से उनका विदाई लेना तय है और पूर्ण संन्यास भी संभव है। ओचोआ ने कहा, संन्यास लेना निश्चित रूप से कठिन होता है, लेकिन मेरे मामले में यह इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैंने लंबे समय तक इस खेल का आनंद लिया है। एक समय आता है जब आपका मन और शरीर कहता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, और फिर आप संतोष के साथ विदा लेते हैं—मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ओचोआ उन चार मेक्सिकन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने पांच विश्व कप खेले हैं। इस सूची में एंटोनियो काबार्जाल, राफेल मार्केज और आंद्रेस गुआडाडो भी शामिल हैं। यदि वह 2026 विश्व कप में खेलते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की तरह छह विश्व कप खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ओचोआ को युवा गोलकीपर राउल टाला रेंगल के बैकअप के रूप में देखा जा रहा है।

फीफा विश्व कप 2026: ईरान की भागीदारी की पुष्टि

अमेरिका में ही खेलेगा अपने मैच

एजेंसी (हि.स.)
वैंकूवर

विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि ईरान फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लेगी और अपने मैच अमेरिका में ही खेलेगी। फीफा अध्यक्ष ने वैंकूवर में आयोजित वैश्विक फुटबॉल महासंघ की कांग्रेस के दौरान यह घोषणा की। इन्फेंटिनो ने अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कहा, मैं शुरूआत में ही यह पुष्टि करना चाहता हूं कि ईरान निश्चित रूप से फीफा विश्व कप 2026 में भाग लेगा और अपने मैच संयुक्त राज्य अमेरिका में खेलेगा।

48 टीमों वाला बड़ा टूर्नामेंट

फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में 11 जून से 19 जुलाई तक होगा। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे टीमों और अधिकारियों को विभिन्न देशों के बीच लगातार यात्रा करनी होगी। ऐसे में वीजा और कूटनीतिक संबंधों को लेकर चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

फोटोः हि.स.

ईरान ने लगातार चौथी बार किया क्वालीफाई

ईरान ने एशियाई क्वालीफायर के तीसरे चरण में ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लगातार चौथी बार विश्व कप के लिए जगह बनाई है। हालांकि, ईरान फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष मेहदी ताज ने अमेरिका और इजराइल के साथ तनावपूर्ण हालात को लेकर चिंता जताई है।

ग्रुप-जी में कड़ी टक्कर

ईरान को ग्रुप-जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। टीम के मुकाबले अमेरिका के लॉस एंजेलिस और सिएटल में खेले जाएंगे। अगर अमेरिका और ईरान अपनी-अपनी ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हैं, तो दोनों टीमें 3 जुलाई को डलास में होने वाले नॉकआउट मुकाबले में आमने-सामने आ सकती हैं।

वैकल्पिक स्थल की मांग खारिज

ईरान ने अमेरिका में मैच खेलने के बजाय वैकल्पिक स्थल की मांग की थी, लेकिन फीफा ने इसे खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरानी खिलाड़ियों को विश्व कप में भाग लेने की अनुमति होगी, लेकिन उनके साथ ऐसे व्यक्तियों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनका संबंध ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से हो।

कंधे की चोट कारण एक महीने तक नहीं खेल पाएंगे सैंटनर

एजेंसी (हि.स.)
ऑकलैंड

न्यूजीलैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान मिशेल सैंटनर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान कंधे में लगी चोट के कारण कम से कम एक महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। इस 34 वर्षीय खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच 23 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं कंधे में चोट लग गई थी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने शुक्रवार को कहा, सैंटनर इस सप्ताह न्यूजीलैंड लौट आए हैं और आज सुबह एक विशेषज्ञ से मिले, जिन्होंने बताया कि उन्हें कम से कम एक महीने के आराम और 'रिहैबिलिटेशन' की जरूरत है। सैंटनर ने आईपीएल मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सीएसके के कार्तिक शर्मा का डाइव लगाकर कैच लिया, लेकिन इस दौरान उनके कंधे और सिर में चोट लग गई। इस कारण वह आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। एनजेडसी ने कहा, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में किया जाएगा। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र चार दिवसीय टेस्ट मैच 27 मई को बेलफास्ट में शुरू होगा। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स (4-8 जून), द ओवल (17-21 जून) और ट्रेंट ब्रिज (25-29 जून) में तीन टेस्ट मैच खेलेगी।

दर्पण मनोरंजन

ऑस्कर ट्रॉफी को 'हथियार' समझ बैठी एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कार्गो में भेजा तो अवॉर्ड हुआ गायब

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा सम्मान 'ऑस्कर' को लेकर न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना घटी है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रूस के मशहूर फिल्ममेकर पाशा तलांकिन, जिन्होंने इस साल अपनी फिल्म के लिए सुनहरी ट्रॉफी जीती थी, अब उसी अवॉर्ड को वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को 'संभावित हथियार' मानकर फिल्ममेकर को इसे साथ ले जाने से रोक दिया, जिसके बाद यह अवॉर्ड ही गायब हो गया।

क्या है पूरा मामला

रूस के फिल्ममेकर पाशा तलांकिन ने इस साल की बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री 'मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन' के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीता था। मार्च में अवॉर्ड जीतने के बाद से वे कई बार अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में जब वे न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां की सुरक्षा जांच ने उन्हें रोक लिया। सुरक्षाकर्मियों का तर्क था कि करीब 3.8 किलो वजन वाली यह ठोस सुनहरी ट्रॉफी एक 'हथियार' के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। तलांकिन ने अधिकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह एक विश्वप्रसिद्ध अवॉर्ड है, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इसे हैंड-बैगेज में ले जाने की अनुमति नहीं दी।

मजबूरी में कार्गो में भेजा, वहीं से हुआ 'लापता'

सिक्योरिटी के अड़ियल रुख के बाद, फिल्ममेकर के पास ट्रॉफी को कार्गो (चेक-इन बैगेज) में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एयरलाइन के कर्मचारियों ने मदद का आश्वासन देते हुए ट्रॉफी को एक सुरक्षित बॉक्स में पैक किया और कार्गो में डाल दिया। हालांकि, जब तलांकिन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के बाद पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। उनका कीमती बॉक्स तो मिला, लेकिन उसके अंदर से ऑस्कर ट्रॉफी गायब थी।

एयरलाइन और अथॉरिटी ने जताया खेद

इस घटना के बाद फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रॉबिन हेसमैन ने सोशल मीडिया और एयरलाइन अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। रॉबिन के अनुसार, एयरलाइन के पास बॉक्स के शिपमेंट का रिकॉर्ड तो है, लेकिन ट्रॉफी कहां गई, इसका कोई जवाब नहीं है। बढ़ते दबाव के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित एयरलाइन ने आधिकारिक बयान जारी कर फिल्ममेकर से माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रॉफी को 'हथियार' समझना एक भूल थी। फिलहाल अथॉरिटी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ट्रॉफी न्यूयॉर्क में ही रह गई या रास्ते में चोरी हुई।

सिनेमा जगत में चर्चा का विषय

सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद लोग अमेरिकी एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि जिस ट्रॉफी को पाना हर फिल्ममेकर का सपना होता है, उसे 'हथियार' समझ लेना समझ से परे है। पाशा तलांकिन अभी भी अपने उस सम्मान का इंतजार कर रहे हैं, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर हासिल किया था। फिलहाल, फिल्ममेकर और उनकी टीम को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव और जांच के बाद उनका ऑस्कर उन्हें सुरक्षित वापस मिल जाएगा।

'किंग' के सेट से सामने आई दीपिका की तस्वीरें, प्रेग्नेंसी में भी कर रही शूटिंग

दीपिका पादुकोण ने हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद वह काम से पीछे नहीं हट रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी और शाहरुख खान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो फिल्म 'किंग' के सेट से बताए जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इन दिनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन में चल रही है। वायरल तस्वीरों में दीपिका नारंगी रंग की फ्लोई ड्रेस में नजर आ रही हैं, जबकि शाहरुख धारीदार शर्ट और काली पैंट में दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक गाने की शूटिंग करते हुए हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री एक बार फिर फैंस को आकर्षित कर रही है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने दोनों के स्टाइल और केमिस्ट्री की तारीफ की है। काम की बात करें, तो दीपिका 'किंग' के अलावा फिल्म 'राका' में भी नजर आएंगी, जिसमें वह अल्लू अर्जुन के साथ दिखाई देंगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में एक्शन दृश्यों के लिए उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है।

जुनैद खान की 'एक दिन' को दर्शकों ने बताया औसत रीमेक, क्या साई पल्लवी का जादू बचा पाएगा फिल्म

जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। 'महाराज' के बाद जुनैद एक बार फिर दर्शकों के सामने हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। आमिर खान प्रोडक्शन के तले बनी यह फिल्म एक थाई फिल्म का आधिकारिक रीमेक है, जिसे लेकर एक्स (पहले ट्विटर) पर रिव्यूज की बाढ़ आ गई है। जहां कुछ लोग कहानी की सादगी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं ज्यादातर यूजर्स रीमेक कल्चर और जुनैद की एक्टिंग स्किल्स को लेकर असंतुष्ट दिखे। फिल्म की कहानी 'दिनेश' (जुनैद) और 'मीरा' (साई पल्लवी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो ऑफिस कुलीग हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब जापान ट्रिप के दौरान मीरा अपनी याददाश्त खो देती है और उसे लगता है कि दिनेश ही उसका बॉयफ्रेंड है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, यह फिल्म याद दिलाती है कि कमजोर कास्टिंग पूरी कहानी को बर्बाद कर सकती है। यूजर्स का कहना है कि जुनैद ने एक दब्बू लड़के का किरदार निभाया तो है, लेकिन उनके अभिनय में गहराई की कमी दिखी। उनके डायलॉग डिलीवरी को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।

साई पल्लवी की हिंदी और जुनैद की 'नेपो किड' इमेज

साउथ की सुपरस्टार साई पल्लवी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। उनके अभिनय की तारीफ तो हुई है, लेकिन उनकी हिंदी को लेकर सोशल मीडिया बंट गया है। एक यूजर ने कहा, अगर साई पल्लवी इसी तरह तमिल लहजे वाली हिंदी बोलती रहीं, तो 'रामायण' फिल्म को लेकर चिंता बढ़ जाएगी। वहीं, आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा बार-बार रीमेक बनाने पर भी सवाल उठे। एक नाराज यूजर ने कमेंट किया, बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलता के बाद भी जुनैद को मौके मिल रहे हैं, यह साफ तौर पर नेपोटिज्म है। आमिर खान प्रोडक्शन से हमें ओरिजिनल कंटेंट की उम्मीद थी, रीमेक की नहीं। हालांकि, हर कोई निराश नहीं है। फिल्म के कुछ प्रशंसकों ने इसे एक 'दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी' बताया है। एक यूजर ने लिखा, साई पल्लवी ने अपनी भावनाओं से दिल जीत लिया और जुनैद का शर्मीला अंदाज काफी हद तक किरदार के साथ न्याय करता है। 'एक दिन' के शुरूआती रिव्यूज को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। दर्शकों की मुख्य शिकायत फिल्म के रीमेक होने और धीमी रफ्तार से है। अब देखना यह होगा कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई और वर्ड-ऑफ-माउथ इसे फ्लॉप होने से बचा पाता है या नहीं।

पंचकूला ने लू के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारियां तेज कीं

उपायुक्त सतपाल शर्मा ने लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की, विभागों को दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने आज सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गर्मी के मौसम में लू के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जारी एडवाइजरी को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु तुरंत कार्रवाई करें।

उन्होंने ये निर्देश लघु सचिवालय में आयोजित वर्ष 2026 के लिए लू से निपटने की तैयारियों और बचाव उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उपायुक्त ने कहा कि राज्य में लू की आशंका को देखते हुए समय पर और आपसी समन्वय के साथ तैयारियां शुरू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, जिसे सभी विभाग गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ लागू करें।

विभागवार समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि वे शहरी स्थानीय निकायों तथा विकास एवं पंचायत विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बस स्टैंड, बाजार, अस्पतालों, सरकारी संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही, पानी के टैंकरों की सूची तैयार कर उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाए जहां पानी की कमी या अधिक भीड़भाड़ रहती है।

बिजली विभाग को निर्देश दिए गए कि वह ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाए और अस्पतालों व अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को भी विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में ओआरएस पैकेट, जीवन रक्षक दवाएं, आईवी फ्लूड, आइस पैक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लू प्रभावित मरीजों के लिए विशेष वार्ड या बेड आरक्षित करने को कहा गया। स्वास्थ्य कर्मियों–चिकित्सकों, नर्सों, फील्ड वर्करों, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं–को हीट-संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए प्रशिक्षित करने के भी निर्देश दिए गए। पशुपालन एवं डेयरी विभाग को लू के दौरान पशुओं की देखभाल हेतु क्या करें और क्या न करें विषय पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पशुओं के लिए छायादार आश्रय, स्वच्छ पेयजल, चारा एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग को अग्निशमन वाहनों और उपकरणों की तत्परता से जांच करने तथा सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि स्कूल परिसरों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाए, गर्मी के चरम समय में बाहरी गतिविधियों से परहेज किया जाए तथा कक्षाओं में उचित वेंटिलेशन और शीतलन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कृषि एवं किसान कल्याण, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, महिला एवं बाल विकास, श्रम तथा पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों को भी लू से निपटने के सभी उपायों को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास और पंचायत अधिकारी श्री विशाल पराशर, जिला वन अधिकारी श्री विशाल कौशिक, परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबंधन) श्रीमती अंजू राणा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री समीर शर्मा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता श्री नरेंद्र अटवाल, उप सिविल सर्जन डॉ. अरविंद सहगल, नायब तहसीलदार पंचकूला श्री हरदेव कुमार, नायब तहसीलदार मोरनी श्री प्रद्युम्न, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चंडीगढ़-पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने मई दिवस पर मानव श्रृंखला बनाई

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (सीपीयूजे) ने आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित सिटी सेंटर में एक मानव श्रृंखला बनाकर रैली का आयोजन किया। विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इस रैली का उद्देश्य कार्यरत पत्रकारों की चिंताओं को उजागर करना और प्रेस की स्वतंत्रता तथा श्रमिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना था।

सीपीयूजे के अध्यक्ष और इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (आई जे यू) के महासचिव विनोद कोहली ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने, उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एक लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए पत्रकारों के बीच एकता का आान किया।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रतिभागियों ने एकजुटता दिखाते हुए एक-दूसरे का हाथ थामकर एक मानव श्रृंखला बनाई, जो मीडिया बिरादरी की एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक थी। मई दिवस विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों के संघर्षों और उपलब्धियों की याद दिलाता है। उन्होंने पत्रकारों के कल्याण और गरिमा के लिए आवाज उठाते रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

श्री कोहली ने प्रेस परिषद का नाम बदलकर 'मीडिया परिषद' करने और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित मुद्दों को हल करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने प्रेस परिषद (भारत) के दिशानिदेर्शों के अनुसार, चंडीगढ़ और पंजाब में प्रेस एक्रीडेशन कमेटी के तत्काल पुनर्गठन पर भी जोर दिया।

इससे पहले, उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों सहित सभी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग की थी। यह रैली एकजुटता और एकता के एक सशक्त संदेश के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने किया क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ का दौरा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता ने दिनांक 30.04.2026 को क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ का दौरा किया। क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ आगमन पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का गॉर्ड ऑफ हॉनर के साथ स्वागत किया गया तत्पश्चात कार्यपालक निदेशक श्री आदित्य गौतम ने शॉल व टोपी पहना कर परंपरागत रूप से उनका अभिनंदन किया।

अपने दौरे के दौरान उन्होंने कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें संबोधित किया। उन्होंने एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं में चल रही निर्माण गतिविधियों की प्रगति पर प्रकाश डाला और कर्मचारियों को समर्पण, प्रतिबद्धता एवं उत्कृष्टता के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कर्मचारियों से उनके सुझाव एवं कार्य से संबंधित समस्याओं को भी आमंत्रित किया, जिससे कर्मचारी कल्याण एवं सकारात्मक कार्य-संस्कृति को बढ़ावा मिले।कार्यक्रम का समापन क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ के कार्यकारी निदेशक, श्री आदित्य गौतम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस दौरान समूह महाप्रबंधक (विधि) श्रीमती रूबी रैना, महाप्रबंधक (तकनीकी) श्री रजब हुसैन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पेक ने अचीवर्स अवॉर्ड फंक्शन 2026 में छात्र उत्कृष्टता का किया सम्मान

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ के डीन स्टूडेंट अफेयर्स (डीएसए) कार्यालय द्वारा अचीवर्स अवॉर्ड फंक्शन 2026 का आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों–शैक्षणिक, खेल, तकनीकी गतिविधियों, एनसीसी एवं सांस्कृतिक आयोजनों–में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करना था। इस समारोह में पेक के माननीय निदेशक प्रो. राजेश कुमार भाटिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ डॉ. डी.आर. प्रजापति, डीन स्टूडेंट अफेयर्स; डॉ. शोभना धीमन (एडीएसए, हॉस्टल्स); एवं डॉ. एम.पी. गर्ग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संकाय सदस्य, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे और उन्होंने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की। डीन स्टूडेंट अफेयर्स डॉ. डी.आर. प्रजापति ने कहा कि ये पुरस्कार केवल सफलता का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि छात्रों की मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में पीईसी के छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की पेक के निदेशक प्रो. राजेश कुमार भाटिया ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उत्साह और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां न केवल आपकी प्रतिभा को दशार्ती हैं, बल्कि टीमवर्क, समर्पण और ईमानदारी जैसे मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करती हैं। उन्होंने छात्रों को हमेशा उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने और पूरे जुनून के साथ भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। इसके उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 277 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 237 छात्र तथा विभिन्न क्लबों, सेल्स, एनसीसी, एनएसएस, खेल और तकनीकी सोसायटियों से जुड़े 40 छात्र सचिव एवं संयुक्त सचिव शामिल थे।

आस्था और ऊर्जा का दिव्य संगम निरंकारी यूथ फोरम के युवा खेलों ने जगाई नई प्रेरणा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़ /पंचकुला /कुल्लू

निरंकारी यूथ फोरम के खेलों का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मनमोहक स्थल ढालपुर मैदान में परम श्रद्धेय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सान्निध्य में हुआ। यह आयोजन निरंकारी यूथ फोरम द्वारा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त सहयोग से संपन्न हुआ, जिसने क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली से सेवादल सेवा के लिए गए हुए है।

कार्यक्रम का शुभारंभ सतगुरु के पावन करकमलों द्वारा ध्वजारोहण एवं मशाल प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसने पूरे वातावरण को उत्साह, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रेरणा से आलोकित कर दिया। युवाओं का जोश, अनुशासन और समर्पण इतना प्रभावशाली था कि शाबाश के स्वर से समूचा परिसर गुंजायमान हो उठा। सतगुरु माता जी ने अपने आर्शीवचनों में फरमाया कि ये खेल केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि नृत्य-व्यम के भाव के साथ अपने शरीर को निरंकार की सेवा में समर्पित करने का एक पावन अवसर हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि दातार की कृपा से पूरे आयोजन में उत्कृष्ट समन्वय और एकजुटता देखने को मिली, भले ही कुछ खेल परिस्थितियों के कारण स्थगित करने पड़े।

इस आयोजन का विशेष महत्व इस बात में निहित है कि यह युवाओं को आध्यात्मिकता, अनुशासन, सेवा और एकत्व के मूल्यों से जोड़ता है। यह एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी मंच है, जहाँ बेरंग में अनेक रंग की भावना साकार होती है-अर्थात विविधता में एकता का जीवंत संगम।

कार्यक्रम के दौरान टीमवर्क और सामूहिकता का सशक्त संदेश दिया गया कि सच्ची जीत वही है, जिसमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। साथ ही युवाओं को प्रेरित किया गया कि वे तन, मन और धन से सेवा भाव बनाए रखें तथा निरंकारी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर उसे सार्थक और सफल बनाएं।

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 4, 11, 18 और 25 मई को

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 04, 11, 18 और 25 मई को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।

संक्षिप्त-समाचार

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को समाधान शिविर में आई समस्याओं का बिना विलंब किए समाधान करने के दिए निर्देश

पंचकूला। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की व उनकी समीक्षा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को बिना विलंब के समाधान शिविर की सभी तरह की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान शिविर में प्रमुखता से समाधान किया जा रहा है। शेष बची लंबित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों की समीक्षा की और जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिलावासी अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान न हों। इस कार्य में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित समस्याओं का अगली बैठक तक समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम सयंम गर्ग, नगराधीश जागृति, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ईओ सुरेंद्र सिंह, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, जिला बागवानी विभाग, पुलिस विभाग, नायब तहसीलदार, खेल विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

पंचकूला जिला की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 35592 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 23420 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4744 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 13083 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7830 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8385 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1550 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 3716 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 6794 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 6674 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 5506 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 730 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

क्लीयरमेडि बाहरा मल्टीस्पेशलिएिटी हॉस्पिटल ने एडवांस्ड 247 ट्रॉमा सेंटर शुरू किया

मोहाली। क्लीयरमेडि बाहरा मल्टीस्पेशलिएिटी हॉस्पिटल (सीबीएमएच) ने मोहाली में अपना अत्याधुनिक 247 ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू किया है, जो एडवांस्ड इमरजेंसी हेल्थकेयर सर्विसेज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। एनएच-21 (खरड़-कुराली) पर स्थित यह अस्पताल गंभीर आपात स्थितियों के दौरान, विशेष रूप से महत्वपूर्ण 'गोल्डन आवर' के भीतर, तुरंत, विशेष और जीवन-रक्षक देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नई सुविधा के बारे में जानकारी मीडिया के साथ कमांडर नवनीत बाली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ, क्लीयरमेडि हेल्थकेयर; रितु रूहेला, फैसिलिटी डायरेक्टर; श्री विवान गिल, क्लस्टर हेड; डॉ.गुनीत सोढ़ी, मेडिकल सुप्रीटेंडेंट और वरिष्ठ विशेषज्ञों झ डॉ.आशीष ठाकुर, न्यूरोसर्जन; डॉ.संदीप कौर, न्यूरोलॉजिस्ट; डॉ.हरि मोहन शर्मा, ऑथोर्पेडिक सर्जन; डॉ.हरदीप सिंह, जनरल और लैपरोस्कोपिक सर्जन; डॉ.रूपाली लाहौरिया, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट; डॉ.गुरजीत कौर, इमरजेंसी हेड; और डॉ.भारती तंवर, प्लास्टिक सर्जन ने साझा की। इस अवसर पर बोलते हुए, कमांडर नवनीत बाली ने कहा कि यह एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर समय पर, हाई-क्वालिटी इमरजेंसी केयर प्रदान करने के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है। विश्व-स्तरीय बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और मौके पर उपलब्ध त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों के साथ, हमारा लक्ष्य गंभीर मामलों में जीवित रहने की संभावनाओं में महत्वपूर्ण सुधार करना है।

नेशनल मून राइट्स , सोशल जस्टिस कॉन्सिल ऑफ इंडिया -चंडीगढ़ ने मनाया लेबर डे

चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय लेबर डे के उपलक्ष्य में नेशनल मून राइट्स, सोशल जस्टिस कॉन्सिल ऑफ इंडिया - चंडीगढ़ ने लेबर चौक पर मजदूर साथियों के साथ उनके हक के प्रति जागरूक करके मनाया।चंडीगढ़ के प्रधान एस ए खान के दिशानिर्देश अनुसार वाइस चेयरमैन मानव शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव शर्मा ने कहा कि लेबर डे (मजदूर दिवस) या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, जो मजदूरों के अधिकारों, सम्मान और उनके संघर्षों को समर्पित है।मजदूर दिवस केवल महज एक दिन नहीं बल्कि उन करोड़ों मजदूरों के संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया।यह दिन समाज में समानता लाने और आर्थिक प्रगति की रीढ़ कहे जाने वाले कामगारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महापर्व है। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी जीशान उल हक, संस्था के फाइनेंस सेक्रेटरी संजीव कपूर, स्टेट कॉर्डिनेटर राकेश शर्मा, गुलशन वर्मा, स्टेट ज्वाइंट सचिव रणदीप सिंह सहारन और मीडिया सेक्रेटरी अजय चौधरी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला ने कार्यक्रम आयोजित किया

श्रमिकों और कामगारों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला ने श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। ये कार्यक्रम सेक्टर-20 स्थित श्रम भवन और पंचकूला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वीनस इंडस्ट्रीज में आयोजित किए गए, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भर में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। यह जानकारी पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, श्री अजय कुमार घांघस ने दी।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों और कामगारों को उनके कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विभिन्न कानूनों के तहत उनके लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी उपायों के बारे में शिक्षित करना था। बड़ी संख्या में श्रमिकों, कर्मचारियों और आम जनता के सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

सेक्टर-20 स्थित श्रम भवन में, एक संवादात्मक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों और सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य परिस्थितियों से संबंधित प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया। उछरअ द्वारा पात्र व्यक्तियों–जिनमें श्रमिक, महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं–को प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं पर भी विशेष जोर दिया गया।

पंचकूला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वीनस इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह का एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ श्रमिकों को उनके शोषण, मजदूरी में देरी और असुरक्षित कार्य वातावरण के खिलाफ उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया। उन्हें शिकायत निवारण तंत्र और सभी के लिए न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका के बारे में भी जागरूक किया गया।

श्रम अधिकारों और कानूनी जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। प्रतिभागियों ने तख्तियां ले रखी थीं और ऐसे नारे लगाए, जिनमें 'श्रम की गरिमा', 'उचित मजदूरी' और 'सुरक्षित कार्य परिस्थितियों' के महत्व को रेखांकित किया गया था। इस रैली का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचना और जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करना था।

इन कार्यक्रमों के दौरान श्रम विभाग के सहायक निदेशक श्री रोहित बेरी और श्रम निरीक्षक श्री कृष्ण सैनी भी उपस्थित थे। उन्होंने श्रमिकों को संबोधित किया और श्रम कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रमिकों को प्रोत्साहित किया कि यदि उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होता है, तो वे आगे आएं और सहायता प्राप्त करें।

श्री अजय कुमार घांघस ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि यह श्रमिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने की याद दिलाने वाला दिन भी है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि उछरअ पंचकूला यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि जागरूकता या संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

इन कार्यक्रमों का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि वे श्रम अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखेंगे और एक न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करेंगे।